हिन्दी, उर्दू, पंजाबी में एक साथ प्रकाशित दिल्ली सरकार की पत्रिका

अंकः नवंबर–दिसंबर 2016

दिल्ली

ਦਿੱਲੀ

دلّی

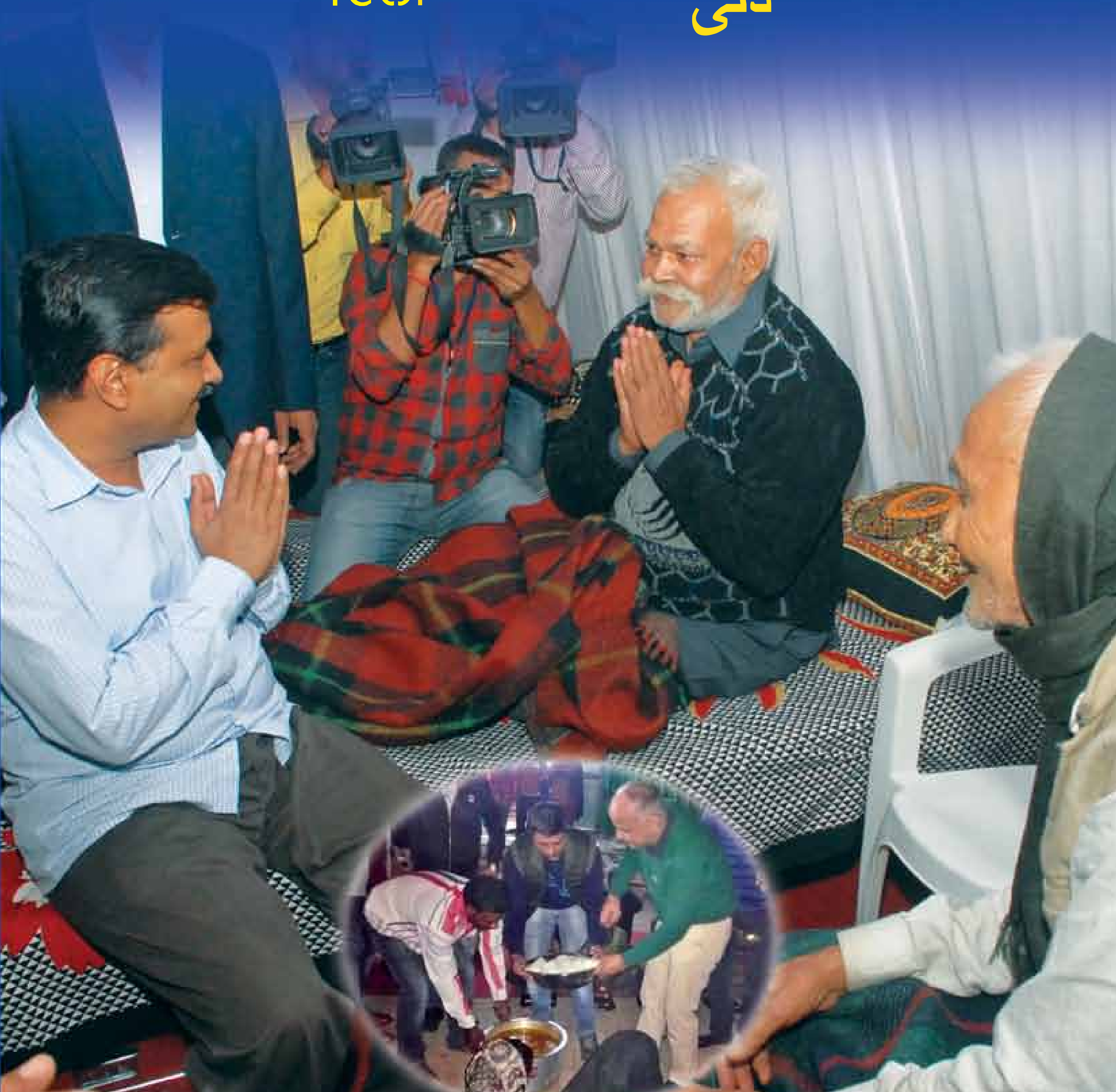

दिल्ली

अंक : नवम्बर–दिसम्बर 2016

प्रधान सम्पादक
डॉ. जयदेव षड़ंगी
विशेष निदेशक
संदीप मिश्र
सम्पादक
डॉ. पंकज श्रीवास्तव
सूचना अधिकारी
शक्तिप्रदा रथ
छाया चित्र
सुधीर कुमार, अजय कुमार, योगेश जोशी

"दिल्ली" पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार रचनाकारों के अपने हैं तथा दिल्ली सरकार का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं।

पत्राचार का पता
प्रधान सम्पादक
दिल्ली सूचना एवं प्रसार निदेशालय
दिल्ली सरकार
खंड सं. 9, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054
दूरभाष : 23819046, 23817926
फैक्स : 23814081
ई–मेल : delhidip@gmail.com

पृथ्वीराज का 'दिल्ली सूत्र' **24**

इस अंक में...

हिन्दी

अक्षरों से दोस्ती, पाठ से प्यार! 2
दिल्ली के अस्पतालों में मुफ़्त होगा एमआरआई और सीटी स्कैन! 5
ग़रीबों के लिए रैनबसेरा और तीन वक़्त का भोजन! 11
शिक्षा को साम्प्रदायिकता के जहर से बचाना होगा–मनीष सिसोदिया 13
एमसीडी स्कूलों के बच्चों का एडमीशन होगा आसान 15
समकालीन वैश्विक संकट के पीछे धर्म है या राजनीति? 16
जातियाँ और उनका अस्तित्व ही राष्ट्र–विरोधी है–डॉ. अंबेडकर 18
वह अनुपम आदमी! 19
आज़ादी की नई उड़ान है स्त्री लेखन! 22
एक स्त्री के विलाप में गूँजा सदियों का जुल्म! 27
संक्षेप में 28

पंजाबी

ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ, ਪਾਠ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ! 1
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਐਮਆਰਆਈ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ! 4
ਐਮਸੀਡੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਾਨ 7
ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੈਅ ਤਨਖਾਹ, ੮ ਛੁੱਟੀਆਂ ! 8
ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ-ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਯਾ 11
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹਾਦੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵੀਰਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ 12
ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਲਾਪ ਵਿਚ ਗੂੰਜਿਆ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ! 13
ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ 14

उर्दू

لفظوں سے دوستی، سبق سے پیار! 1
دہلی کے نجی اسپتالوں میں مفت ہوگا ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین! 4
ایم سی ڈی اسکولوں کے بچوں کا داخلہ ہوگا آسان 7
گیسٹ ٹیچروں کو ملے گا طے تنخواہ، 8 چھٹیاں! 8
تعلیم کو فرقہ واریت کے زہر سے بچانا ہوگا۔ منیش سسودیا 11
ایک لڑکی کے بچھڑنے کے غم میں گونجا صدیوں کا ظلم! 13
مختصر میں 14

शानदार रहा 'हर बच्चा पढ़ सकता है' अभियान

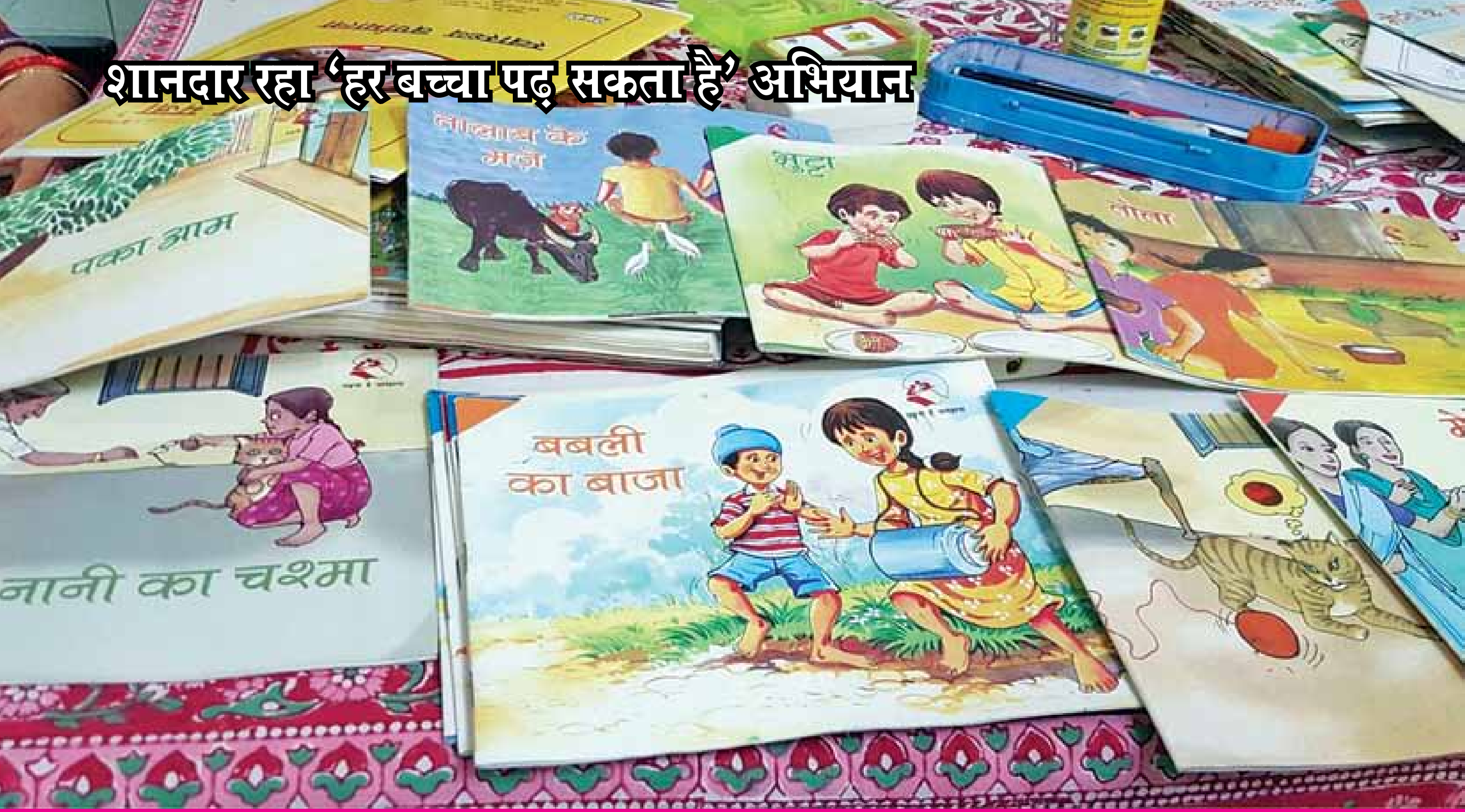

अक्षरों से दोस्ती, पाठ से प्यार!

सरकारी स्कूलों के 3.5 लाख बच्चों ने जाना 'पढ़ने' का मतलब

"मेरे ग्रुप में तीन बच्चे ऐसे हैं जो दो हफ्ते पहले सिर्फ अक्षर पहचान पाते थे और अभी भी उनका वही हाल है. जबकि बाकी बच्चे तेजी से आगे बढ़ गए हैं। ऐसे में मैं क्या करूँ ?" – व्हाट्स ऐप ग्रुप में एक शिक्षक ने दूसरे शिक्षकों को अपनी परेशानी बताई।

"हमारे स्कूल का एक बच्चा पिछले एक हफ्ते से स्कूल नहीं आ रहा है। स्कूल रिकॉर्ड में उसके पिता का जो फोन नंबर दर्ज है, वह अब काम नहीं कर रहा है। क्या आप उस बच्चे को स्कूल वापस लाने में मदद कर सकते हैं ?" – एक शिक्षक ने एसएमसी (स्कूल मैनेजमेंट कमेटी) के सदस्य से पूछा।

"अब मैं रोज स्कूल आता हूँ क्योंकि मेरे टीचर मुझे नाम से बुलाते हैं"– कक्षा सात के एक छात्र ने स्कूल में आ रहे बदलाव को इस तरह से समझा।

"मैं खुद नहीं पढ़ सकती लेकिन अपने बेटे से अखबार पढ़वाकर सुनती हूँ। मुझे एक महीने में काफी फर्क दिख रहा है। अब वह ज्यादा आत्मविश्वास के साथ पढ़ता है "– कक्षा छह के एक बच्चे की माँ ने खुशी जाहिर की।

" मैं गणित का शिक्षक हूँ और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को विज्ञान पढ़ाता हूँ। मैं सोचता था कि अगर बच्चे किताब पढ़ नहीं पाते तो इसकी चिंता हिंदी के अध्यापक की होनी चाहिए, इससे मेरा क्या लेना–देना। बहरहाल, प्रधानाचार्य ने कक्षा आठ के दस लड़कों को पढ़ने में सक्षम बनाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी जिसे मैंने बड़े बेमन से स्वीकार किया था। लेकिन अब मुझे महसूस हुआ कि यह एक अवसर था जिसने मुझे बच्चों को समझने में मदद की। बच्चे ठीक से पढ़ना सीख लेंगे तो मेरे विषय को भी बेहतर तरीके से समझ पायेंगे।"

बदली कक्षा 6, 7 और 8 की सूरत !

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षा छह, सात और आठ में पढ़ने वाले कुल बच्चों की तादाद है 6,32,370। 'हर बच्चा पढ़ सकता है' अभियान के तहत इसके 57 फीसदी यानी 3,59,152 बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया गया जिनकी हिंदी में लिखा पाठ पढ़ लेने की क्षमता कम थी। 5 सितंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच चले इस अभियान के नतीजे उत्साहवर्धक रहे–

कक्षा 6 –

- दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षा छह में पढ़ने वाले 25 फीसदी बच्चे ही धड़ल्ले से अपनी किताब पढ़ लेते थे। अभियान के बाद ऐसे बच्चों की तादाद 46 फीसदी हो गई।
- 32 फीसदी बच्चे ऐसे थे जो कक्षा एक की किताब का भी एक पैरा नहीं पढ़ सकते थे। अभियान के बाद ऐसे बच्चों की तादाद घटकर 14 फीसदी रह गई।
- अक्षर भी नहीं पहचान सकने वाले बच्चों की तादाद 8 फीसदी से घटकर 2 फीसदी रह गई।

कक्षा 7–

- कक्षा सात के 52 फीसदी ही पढ़ने में सक्षम थे। अभियान के नतीजे में यह आँकड़ा 64 फीसदी हो गया।
- 24 फीसदी ऐसे बच्चे भी थे जो कक्षा 1 के स्तर की किताब का भी एक पैरा नहीं पढ़ सकते थे। यह आँकड़ा घटकर 10 फीसदी रह गया।
- अक्षर भी न पहचान सकने वाले बच्चों की तादाद 5 फीसदी से घटकर एक फीसदी रह गई।

कक्षा 8–

- कक्षा आठ के 55 फीसदी बच्चे अपना पाठ पढ़ सकते थे, अभियान के बाद कुल 68 फीसदी बच्चे अपनी किताबें पढ़ने में सक्षम हो गए।
- इस कक्षा के 20 फीसदी बच्चे ऐसे थे जो कक्षा एक के स्तर की किताब नहीं पढ़ पाते थे। अभियान के बाद यह आँकड़ा घटकर 8 फीसदी रह गया।
- कक्षा आठ में पहुँच गए 4 फीसदी बच्चे ऐसे भी थे जिन्हें अक्षर ज्ञान भी नहीं था। यह आँकड़ा महज 1 फीसदी रह गया।

Yogesh Kumar

रीडिंग मेले में खेल खेल में सीखा पढ़ना

■ प्रस, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार के एजुकेशनल कैंपेन 'रीडिंग मेले' में रविवार को स्टूडेंट्स अपने पैरेंट्स के साथ पहुंचे। सरकार इन मेलों के साथ क्लास 6 से 8 तक के हर बच्चे को अपनी किताबें पढ़ने लायक बनाने की चुनौती को पूरा करने की कोशिश में है। हर बच्चे को पढ़ना सिखाने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर ने टीचर्स डे के दिन बाल दिवस यानी आज की डेडलाइन रखी थी। कैंपेन के तहत हर संडे रीडिंग मेले लगाए गए, करीब 250 मेलों में बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स और उनके पैरेंट्स भी पहुंचे।

स्कूल मैनेजमेंट कमिटी ने इस मेलों को ऑर्गनाइज किया और कई ऐसे टूल और एक्टिविटी का इस्तेमाल किया ताकि बच्चे मजेदार तरीके से पढ़ना सीख सकें। मेलों में तमाम एक्टिविटी और गेम रखे गए ताकि बच्चा अक्षर, शब्द, वाक्य और पैराग्राफ पढ़ना सीख सकें। रविवार को नंद नगरी इलाके में लगे रीडिंग मेले में भी बच्चों ने खेल खेल में पढ़ना सीखा।

यह कुछ उदाहरण हैं जो शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर से लेकर बाल दिवस यानी 14 नवंबर के बीच दिल्ली के कक्षा छह से आठ में पढ़ने वाले सभी स्कूली बच्चों को पढ़ने में सक्षम बनाने के लिए चले व्यापक अभियान के दौरान उभर कर आये। वैसे तो डॉ. राधाकृष्णन और पं. जवाहरलाल नेहरू को समर्पित यह दोनों दिन हर साल आते हैं, लेकिन इस बार दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने इसमें अनोखा रंग भर दिया। देश में अपनी तरह का अनोखा "14 नवंबर 2016 तक सभी बच्चे पढ़ेंगे" अभियान शुरू किया गया। शिक्षक दिवस पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में पूरे शिक्षा विभाग ने शपथ ली कि बाल दिवस तक सभी बच्चों को अबाध गति से हिंदी पढ़ने में सक्षम बना दिया जाएगा।

यह संकल्प शिक्षा की स्थिति पर एक बड़ी टिप्पणी थी। प्राथमिक शिक्षा में पाँच बरस बिताकर आने वाले बच्चों से

यह उम्मीद तो होती ही है कि वे अपनी किताबें पढ़ लेंगे। लेकिन यह विडंबना ही है कि तमाम बच्चे इस कसौटी पर खरे नहीं उतर पाये। जुलाई 2016 में किए गए एक सर्वेक्षण का नतीजा था कि कक्षा छह के 74 फीसदी बच्चे अपनी पाठ्यपुस्तक का भी एक पैरा नहीं पढ़ पाए। यही नहीं, कुल बच्चों के 31 फीसदी ऐसे भी निकले जो कक्षा एक की किताबों में लिखा भी नहीं पढ़ पाए। नो डिटेंशन पालिसी की वजह से कक्षा 7 और 8 में पहुँच गए बच्चों में 50 फीसदी ऐसे थे जो अपनी ही पाठ्यपुस्तक से एक पैराग्राफ नहीं पढ़ पाए।

दूसरी तरफ पाठ्यक्रम यह सोचकर बना है कि बच्चों को पढ़ना आता है। यही नहीं उनसे यह उम्मीद भी की जाती है कि वे पुस्तकों से खुद पढ़कर तमाम बातों को समझ लेंगे। जाहिर है, पढ़ने में सक्षम हुए बगैर कोई छात्र एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता।

यह वजह है कि शिक्षा विभाग ने छात्र–छात्राओं को पढ़ने में सक्षम बनाने के लिए इतना व्यापक अभियान चलाया। अगले कुछ हफ्तों तक सभी स्कूलों के कक्षा छह से आठ के शिक्षकों ने अभिभावकों और समाज के सहयोग से सभी बच्चों को पढ़ना सिखाने का अभियान चलाया। इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया। जनता से अपील की गई कि वह इस अभियान से जुड़े और लोग इर्द–गिर्द के ऐसे बच्चे को मदद करें जो अपनी किताब ठीक से न पढ़ पाता हो। अगले दो महीने तक शिक्षा विभाग के 1016 स्कूलों में कक्षा छह, सात और आठ में नामांकित 6.3 लाख बच्चों में से करीब साढ़े तीन लाख बच्चों को पढ़ने में दक्ष बनाने के लिए शिक्षकों ने जबरदस्त मेहनत की।

इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए 185 शिक्षकों का रिसोर्स ग्रुप बनाया गया जिन्हें 'मेंटर टीचर' कहा गया जिन्हें पाँच स्कूलों की जिम्मेदारी दी गई। इन्होंने निर्धारित स्कूलों के दो शिक्षकों को इस अभियान के लिए तैयार किया जिन्होंने किताबें पढ़ पाने में अक्षम बच्चों पर विशेष ध्यान दिया और विभिन्न तरह के क्रियाकलापों के जरिये उन्हें पढ़ने में दक्ष होने के लिए प्रेरित किया।

इस अभियान का एक शानदार पहलू रीडिंग मेला बतौर सामने आया। इन्हें स्कूलों के अलावा सप्ताहांत में मोहल्लों में भी लगाया गया। एसएमसी के जरिये लोगों को इन मेलों से जोड़ा गया। बच्चों का पढ़ना एक दिलचस्प अनुभव बन गया। अभियान के दौरान कुल 522 रीडिंग मेला आयोजित किए गए। इन मेलों में 20 हजार अभिभावकों और 71000 बच्चों ने भाग लिया।

इसी दौरान स्कूलों में मेगा पीटीएम (पैरेंट टीचर मीटिंग) आयोजित की गई। इनमें अभिभावकों को बच्चों की प्रगति से जुड़ी तमाम बातों के अलावा उनके पढ़ पाने की क्षमता के बारे में भी जानकारी दी गई। ■

'प्रोजेक्ट स्माइल' से चमकेंगे 35 हज़ार बच्चे !

'हर बच्चा पढ़ सकता है' अभियान के बाद दिल्ली सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए 'प्रोजेक्ट स्माइल' शुरू किया है। ये अभियान उन बच्चों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो सिर्फ अक्षर पहचान सकते हैं, लेकिन पाठ पढ़ नहीं पाते। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ऐसे 35,000 बच्चे ऐसे हैं जिन पर इस संबंध में विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

सरकार ने 5 सितंबर से 14 नवंबर के बीच 'हर बच्चा पढ़ सकता है' अभियान चलाया था जिसमें 1 लाख से ज्यादा बच्चे अपनी किताबें पढ़ने लायक बने हैं। सरकार ने इस सिलसिले में रीडिंग मेला समेत कई उपाय किए थे लेकिन बच्चे अक्षर पहचानने से आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसे ही 35,000 बच्चों को पढ़ने में सक्षम बनाने के लिए 'प्रोजेक्ट स्माइल' शुरू किया गया है। विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों को यह जिम्मेदारी दी गई है।

शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि जब हमने 'हर बच्चा पढ़ सकता है' अभियान शुरू किया था, तो कोशिश की थी कि हर जरूरतमंद बच्चे को इसका लाभ मिले। अब 'प्रोजेक्ट स्माइल' के जरिये पक्का किया जाएगा कि एक भी बच्चा छूटने न पाए।

इन बच्चों का स्पेशल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसके बाद उनकी क्षमता के अनुसार अलग–अलग ग्रुप बनाकर उन्हें स्पेशल एजुकेशन टीचर्स और काउंसलर्स को सौंप दिया जाएगा जो खास तकनीक की मदद से उनकी परेशानी दूर करेंगे। शिक्षा निदेशालय में एक कंट्रोल यूनिट होगी जो अभियान पर नजर रखेगी।

आम आदमी को तोहफ़ा

दिल्ली के निजी अस्पतालों में मुफ़्त होगा एमआरआई और सीटी स्कैन!

दिल्ली सरकार के 10 अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीज अब एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी जांच प्राइवेट लैब्स में भी मुफ्त करा सकेंगे। इसके लिए सरकार ने 7 प्राइवेट लैब्स से एग्रीमेंट किया है। कुछ अन्य लैबों को इस स्कीम से जोड़ने पर बात चल रही है।

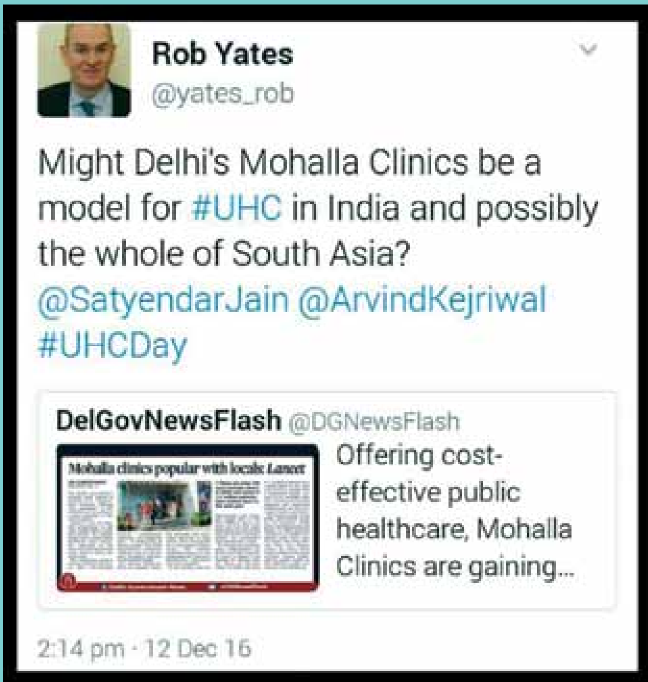

दिल्ली सरकार ने जरूरतमंद मरीजों के लिए फ्री एमआरआई और सीटी स्कैन सुविधा शुरू की है। हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली में फ्लाईओवर बनाने में करोड़ों रुपये बचाए गए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश के मुताबिक इन पैसों का इस्तेमाल लोगों को बेहतर हेल्थ फैसिलिटी देने पर किया जा रहा है। सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दवाइयां और बहुत से टेस्ट तो पहले से ही फ्री हैं, लेकिन एमआरआई और सीटी स्कैन जैसे बड़े टेस्ट भी अब फ्री हो सकेंगे।

अस्पतालों में एमआरआई के लिए तीन–तीन साल की वेटिंग की बात सामने आने के बाद सरकार ने यह फैसला किया है। सरकार चाहती है कि एमआरआई के लिए लिए लोगों को इंतजार न करना पड़े और एक हफ्ते के भीतर एमआरआई और सीटी स्कैन हो जाए। अभी 7 प्राइवेट लैब्स के साथ बात फाइनल हुई है। कुछ और लैब्स के साथ भी बात चल रही है।

हेल्थ मिनिस्टर ने बताया कि दिल्ली आरोग्य कोष गवर्निंग बॉडी की 11वीं मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि

दिल्ली में खुलेंगे सौ डेंटल क्लीनिक

दिल्ली सरकार राजधानी के विभिन्न इलाकों में 100 आम आदमी डेंटल क्लीनिक खोलेगी। मोहल्ला क्लीनिक की तर्ज पर इन क्लीनिकों में छोटी–छोटी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। यदि दिक्कत अधिक होगी तो मरीज को बड़े अस्पताल में भेजा जाएगा।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह बात मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस में आयोजित डेंटल हेल्थ मेले के उद्घाटन मौके पर कही। इस अवसर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि डेंटल कॉलेज के पाँच सेंटर और खोले जाएँगे। उन्होंने कहा कि कि मुंह से जुड़ी बीमारियों में इजाफा हो रहा है, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग अस्पताल तक नहीं पहुंचते, इसीलिए छोटी–छोटी बीमारियों की जांच के लिए डेंटल क्लीनिक खोले जाएंगे। साथ ही मुंह से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इस मौके पर इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल व डायरेक्टर डॉ. महेश शर्मा ने कहा कि इस प्रकार डेंटल क्लीनिक बनाने में इंस्टीट्यूट पूरा सहयोग करेगा।

‘द लॉन्सेंट’ ने सराहा ‘मोहल्ला क्लीनिक’

दुनिया के प्रमुख मेडिकल जर्नल द लान्सेंट ने दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लीनिक योजना की तारीफ की है। ब्रिटेन के इस बेहद प्रतिष्ठित जर्नल का कहना है कि इससे आम लोगों को काफी फायदा हुआ है। इस पहल का मकसद पिछड़ी बस्तियों तक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाना है। देश के दूसरे राज्य भी इस मॉडल को समझ रहे हैं और अपनाने को उत्सुक हैं।

उधर, प्रमुख अमेरिकी अख़बार वाशिंगटन पोस्ट पहले ही मोहल्ला क्लीनिक को एक अनोखा प्रयोग बता चुका है। अख़बार ने यह भी लिखा था कि अमेरिकी सरकार को इससे कुछ सीखना चाहिए।

World Report

Delhi looks to expand community clinic initiative

Sections ☰

The Washington Post

Innovations

What New Delhi’s free clinics can teach America about fixing its broken health care system

दिल्ली के नागरिकों को फ्री एमआरआई–सीटी स्कैन की फैसिलिटी मिलेगी। जो भी दिल्ली में कम–से–कम तीन साल से रह रहे होंगे, वे इस स्कीम का फायदा उठा सकेंगे। जिनकी सालाना फैमिली इनकम तीन लाख तक होनी चाहिए, वे लैब्स में जाकर टेस्ट करवा सकेंगे और उनका पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। अगर किसी के पास फूड सिक्यॉरिटी कार्ड है तो उसमें रेजिडेंस और इनकम प्रूफ होता है।

इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर आईकार्ड, लाइसेंस से भी पता चल सकेगा कि वह कितने दिनों से दिल्ली में रह रहा है।

दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दिल्ली के जो मरीज भर्ती हैं, उन सबको यह फैसिलिटी मिलेगी। हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने बताया कि इस सुविधा का लाभ सिर्फ उन मरीजों को मिलेगा, जो कम से कम तीन साल से दिल्ली में रह रहे हों। राज्य सरकार के 10 अस्पतालों में भर्ती दिल्ली निवासी सभी मरीज प्राइवेट लैब में एमआरआई और सीटी स्कैन करा सकेंगे। ओपीडी में आने वाले सिर्फ वही मरीज इस फैसिलिटी का फायदा उठा पाएंगे, जिनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपये या उससे कम होगी। इसके लिए उन्हें डॉक्टरों का लिखा पर्चा, इनकम और निवास प्रमाणपत्र दिखाने होंगे। ■

गेस्ट शिक्षकों को मिलेगा

अतिथि शिक्षकों को तोहफा देते हुए दिल्ली सरकार ने उन्हें तय वेतन देने का फैसला किया है। जिन अतिथि शिक्षकों ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) ने पास कर ली है उनके वेतन में 90 फीसदी से ज्यादा का इजाफा किया जाएगा। साथ ही उन्हें आठ आकस्मिक अवकाश भी मिलेंगे।

दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में अतिथि शिक्षकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार ने समान वेतन के लिए समान वेतन देन का जो वादा किया था, उसे पूरा किया जाएगा। इस संबंध में जो भी तकनीकी दिक्कतें हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो साल में दिल्ली में शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं और अब प्राइवेट स्कूलों से बच्चे सरकारी स्कूलों में शिफ्ट होने लगे हैं। इसमें अतिथि शिक्षकों का भी अहम योगदान है।

पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि सरकारी स्कूलों में 8000 नए क्लासरूम मार्च तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा 8000 और क्लासरूम की भी तैयारी शुरू हो गई है।

गौरतलब है कि अतिथि शिक्षकों को अभी तक कोई आकस्मिक अवकाश नहीं मिलता था। स्कूल न आने पर उनका वेतन कटता था। साथ ही उन्हें वेतन दैनिक आधार पर मिलता था। अब उन्हें हर महीने तय वेतन मिलेगा।

सरकार ने सीटेट पास न कर सकने वाले दो हजार अतिथि शिक्षकों के वेतन में भी करीब 44 फीसदी का

तय वेतन, 8 छुट्टियाँ !

इजाफा किया है। जिन प्राइमरी असिस्टेंट टीचर्स को अभी 700 रुपये प्रतिदिन और 17500 रुपये महीने मिलते थे, उन्हें अब 1000 रुपये प्रतिदिन या 25000 रुपये दिए जाएँगे। इसके अलावा 800 रुपये प्रतिदिन और 20000 रुपये महीने पाने वाले टीजीटी शिक्षकों को अब 26,250 रुपये प्रतिमाह दिए जाएँगे। ■

वेतन में 90 फ़ीसदी से ज़्यादा का इज़ाफ़ा

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अतिथि शिक्षकों के संबंध में कैबिनेट के फैसले की जानकारी खुद एक प्रेस कान्फ्रेंस के जरिये दी। अतिथि शिक्षकों को खुशख़बरी देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी 17000 गेस्ट टीचर्स के वेतन में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इनमें करीब 15000 ऐसे हैं जिन्होंने सीटेट पास कर लिया है। इन शिक्षकों को हर महीने तय वेतन मिलेगा। असिस्टेंट प्राइमरी टीचरों (सीटेट) को अभी 700 रुपये प्रतिदिन और 17500 रुपये मासिक वेतन मिलता है। अब उन्हें 33200 रुपये वेतन मिलेगा। वहीं टीजीटी टीचरों को 33,120 मासिक वेतन मिलेगा। उन्हें 800 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान होता था। महीने में उन्हें 20,000 रुपये मिलते थे। तरह पीजीटी पास टीचरों को 34,100 रुपये मासिक वेतन मिलेगा जिन्हें पहले 22500 रुपये या 900 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलते थे।

प्रधानाचार्य को शिक्षक नियुक्त करने का अधिकार

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्यों को अब जरूरत के हिसाब से रिटायर्ड शिक्षकों को नियुक्त करने का अधिकार दे दिया है। शिक्षकों की कमी और मौजूदा शिक्षकों के ट्रेनिंग या छुट्टियों पर जाने की स्थिति में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसलिए ये फैसला लिया गया है।

शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक अगर किसी स्कूल में किसी सब्जेक्ट के टीचर की कमी है, तो अब प्रिंसपल को डिप्टी डायरेक्टर को कहने और फाइल भेजने की जरूरत नहीं होगी। अब स्कूल के स्तर पर ही समस्या का समाधान हो जाएगा।

इसके लिए सरकारी स्कूल से रिटायर्ड टीजीटी और पीजीटी को http://www.edudel.nic पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन में वे अपनी सुविधा के अनुसार स्कूल का चयन कर सकेंगे, फिर संबंधित स्कूल में उनका इंटरव्यू होगा। चयन समिति में प्रिंसिपल, एक टीचर और एसएमसी के दो–तीन सदस्य शामिल होंगे। इस प्रक्रिया के तहत चयन के बाद भी जो रिटायर्ड शिक्षक बच जाएंगे, शिक्षा विभाग उनका एक जिलावार पैनल बनाएगा। भविष्य में जब भी किसी स्कूल को शिक्षकों की जरूरत होगी, तो वो इस पैनल से अपने यहाँ उनकी नियुक्ति कर सकेगा।

इससे पहले दिल्ली सरकार ने हर स्कूल के प्रधानाचार्य को अपने यहां एक एस्टेट मैनेजर नियुक्त करने का अधिकार दिया था। अब दिल्ली के तकरीबन सभी सरकारी स्कूलों की हर पाली में एक–एक एस्टेट मैनेजर हैं। इनका काम स्कूल में साफ–सफाई इत्यादि सुनिश्चित करवाना है। पहले स्कूल में साफ–सफाई सुनिश्चित करवाने का काम प्रधानाचार्य या किसी शिक्षक के जिम्मे होता था और इस वजह से वो बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते थे। ■

नोटबंदी से फैली भुखमरी के ख़िलाफ़ दिल्ली सरकार का मोर्चा

ग़रीबों के लिए रैनबसेरा और तीन वक़्त का भोजन !

न काम हो न पैसे...फिर भी दिल्ली की भीषण ठंड से बचने के लिए सर पर छत और चारपाई–बिस्तर हो। इतना ही नहीं सुबह का नाश्ता और दो वक्त का भोजन भी हो। किसी सर्द रात को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री खुद हालचाल लेने पहुँचे और अपने हाथ से परोस कर खिलाएँ भी। ऐसे में गरीब आदमी दिल्ली सरकार को कितनी दुआएँ देगा, इसका सिर्फ अंदाज ही लगाया जा सकता है।

नोटबंदी की वजह से बेकार हुए गरीबों के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ ऐसी ही संवेदनशीलता दिखाई। पहले तो 10 जगहों पर सजे–धजे रैन बसेरे बनाए गए ताकि कोई बेघर ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर न हो और फिर मुफ्त भोजन सेवा भी शुरू की गई।

रैन बसेरों का इंतजाम तो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन उसमें अहसान का भाव ज्यादा रहता था। केजरीवाल सरकार ने जैसे रैन बसेरे बनवाए उसमें प्यार की खुशबू भी है। सरकार की संवेदनशीलता तब और खुलकर सामने आई जब उसन संकल्प लिया कि नोटबंदी की वजह से दिल्ली में किसी गरीब को भूख से नहीं मरने दिया जाएगा।

सरकार का मानना है कि नोटबंदी की वजह से तमाम लोगों का रोजगार छिन गया। ऐसे लोग अपनी मजदूरी से वंचित हैं। ऐसे भी गरीब हैं जिन्होंने पैसे के अभाव में दम तोड़ दिया या आत्महत्या कर ली। लेकिन इस त्रासदी में भूख शामिल न हो, यह उसकी जिम्मेदारी है।

दिल्ली सरकार की ओर से गीता घाट, यमुना पुश्ता, दांडी पार्क, जामा मस्जिद, सराय काले खां, निजामुद्दीन नीला गुंबद, सराय पुश्ता, झंडेवालान शेल्टर 1, कोटला मुबारकपुर और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास फतेहपुरी में रैन बसेरे बनाए गए और यहाँ भोजन का इंतजाम किया गया। सुबह नाश्ता, दिन में लंच और रात में डिनर की व्यवस्था की गई। खाना सिर्फ उन्हें नहीं खिलाया गया जो रैन बसोरों में रह रहे थे बल्कि आस–पास के गरीब लोगों को भी खाना खिलाया गया।

सरकार की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले दिन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने खुद गीता घाट स्थिति रैन बसेरा पहुंचकर हालचाल लिया। इसके बाद वे दांडी पार्क यमुना बाजार और सराय काले खां के रैन बसेरों में गए। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने खुद अपने हाथ से लोगों को खाना परोसा और मेन्यू भी चेक किया। एक सेंटर पर लोगों के लिए खिचड़ी का इंतजाम किया गया था। दूसरी जगह पर छोले, चावल और रोटी का इंतजाम था। और तीसरी जगह दाल, चावल, रोटी और सब्जी की व्यवस्था की गई थी।

सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए लोगों ने उप–मुख्यमंत्री को परेशानी बताई। कुछ ने बताया कि वे और उनके कुछ साथी शादी–विवाह और अन्य कार्यक्रमों में कैटरिंग में दिहाड़ी काम करते हैं, लेकिन नोटबंदी के बाद न काम है न ही पैसा। किसी दिन काम मिलता है तो लोग 500 रुपये के पुराने नोट दे देते हैं। पहले जहां 10 लोगों को काम पर रखा जाता था अब वहां केवल चार लोग काम पर रखे जा रहे हैं।

पत्रकारों से बातचीत में मनीष सिसोदिया ने कहा कि नोटबंदी की वजह से गरीब मौत के कगार पर खड़े हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ऐसा नहीं होने देगी। दिल्ली सरकार अपनी पूरी ताकत लगाएगी ताकि नोटबंदी की वजह से लोग भुखमरी का शिकार न बनें। उन्होंने कहा कि ठंड बढ़ने के साथ–साथ रैनबसेरों और मुफ्त भोजन की व्यवस्था का भी विस्तार किया जाएगा।

शिक्षा को साम्प्रदायिकता के ज़हर से बचाना होगा-मनीष सिसोदिया

मैं दिल्ली का शिक्षा मंत्री होते हुए भी शिक्षा पर हो रहे इस प्रोटेस्ट में शामिल हूँ तो इसलिए, क्योंकि मुझे भी शिक्षा की चिंता है। मुझे इस बात की चिंता है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ स्कूल खोलना, मिड–डे मील बांटना या कमरे बनवाना नहीं है। शिक्षा का मतलब सिर्फ टीचर्स का एप्वाइंटमेंट करना नहीं है। जिस समय केंद्र की सत्ता में बैठे लोग, पूरे देश में सामाजिक ताने–बाने को तोड़ रहे हैं, जिस तरह से अपनी नीतियों से व्यापार की कमर तोड़ रहे हैं, जिस तरह धर्म और जातियों के नाम पर लड़ाई करवाकर समाज को बांटा जा रहा है, उस सारी साजिश के बीच शिक्षा की भूमिका अहम हो जाती है। लेकिन आज मैं इस चिंता में शामिल होने आया हूँ कि शिक्षा को भी उसी तरह जहरीला बनाने की तैयारी की जा रही है।

साजिश रची जा रही है कि किसी तरह शिक्षा को बदल दो। उसे बर्बाद कर दो। जो जहर राजनीति के जरिये घोलने की कोशिश की जाती रही है, वही जहर एजुकेशन के जरिये घोलने की कोशिश की जा रही है। एजुकेशन में जहर घोलने का मतलब है कि देश की भावी पीढ़ी के

माइंडसेट में स्थायी रूप से ये जहर घोलना। मुझे इस बात की चिंता है कि अगर शिक्षा में ये लोग धर्म और संप्रदाय का जहर घोलने में कामयाब हो गए तो स्कूल और कॉलेजों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मुझे इस बात की चिंता है कि जिन्हें हम स्कूल–कॉलेज कहते हैं, कल उन्हें आरएसएस की शाखा न कहा जाने लगे।

शिक्षा मंत्री होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि देश की यूनिवर्सिटीज, स्कूलों, कॉलेजों को धर्म व जाति की राजनीति का अखाड़ा होने से बचाया जाए। देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू को बदनाम करके रख दिया गया है। आईआईटी और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स से विश्वस्तरीय रिसर्च की खबरें नहीं आ रहीं, बल्कि सरकार और संस्थानों के बीच राजनीतिक टकराव की खबरें आ रही हैं। जो वाइस चांसलर सरकार की नीतियों के आगे घुटने नहीं टेक रहे, जो इनकी मनचाही जहर भरी नीतियों को लागू करने से मना करते हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।

दिल्ली का शिक्षा मंत्री होने के नाते इनका विरोध करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरा विरोध किसी एक समूह, संप्रदाय या धर्म से नहीं है। मेरा मकसद है कि देश के स्कूलों और कॉलेजों को किसी भी जाति–धर्म की राजनीति का अखाड़ा बनने से बचाना। स्कूलों–कॉलेजों में हमें अच्छे इनसान और अच्छे प्रोफेशनल्स तैयार करने हैं, धर्म और जाति में उलझी भीड़ नहीं। भारत के ताने–बाने में मिशनरी स्कूल भी हैं, मदरसे भी हैं और सरस्वती शिशु मंदिर भी हैं। लेकिन भारत के स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम के पीछे की सोच वैज्ञानिक होनी चाहिए। फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए। हमें 50 साल पुराने नहीं, 50 साल आगे के भारत के लोग तैयार करने हैं।

इसलिए ये आवाज उठनी जरूरी है कि हम मिलकर किसी भी ऐसी कोशिश का विरोध करें जो स्कूलों–कॉलेजों को किसी एक धर्म या जाति की शिक्षा का केंद्र बना दे। और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ऐसी किसी भी लड़ाई में मैं आपके साथ हूं।

(केंद्र सरकार की प्रस्तावित शिक्षा नीति के विरोध में 'ज्वाइंट एक्शन कमेटी अगेंस्ट द एंटी–पीपल एजुकेशन पॉलिसी' द्वारा 17 नवंबर को संसद मार्ग पर आयोजित प्रोटेस्ट में दिए गए विचार)

एमसीडी स्कूलों के बच्चों का एडमीशन होगा आसान

सरकारी स्कूल देंगे एमसीडी शिक्षकों और बच्चों को पार्टी

एमसीडी स्कूलों से पाँचवीं पास करने के बाद दिल्ली के सरकारी स्कूलों में प्रवेश चाहने वाले बच्चों का दिल्ली सरकार विशेष अंदाज में स्वागत करेगी। उनके एडमीशन की प्रक्रिया तो सरल होगी ही, एमसीडी स्कूलों के पाँचवीं के शिक्षकों को बुलाकर बच्चों के साथ एक पार्टी भी आयोजित की जाएगी।

दिल्ली सरकार के इस एडमीशन प्लान के मुताबिक अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छठीं कक्षा में एडमिशन के लिए बच्चों और उनके अभिभावकों को स्कूल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल और टीचर्स 15 मार्च से 1 अप्रैल के बीच एमसीडी के स्कूलों में जाएँगे और वहाँ उन बच्चों को एडमिशन स्लिप देकर आएंगे, जिनके एडमिशन उनके स्कूलों में होने हैं। अभिभावकों के पास यह एडमिशन स्लिप होगी और वे स्कूल में जाकर अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकेंगे।

इसके अलावा यह भी तय किया गया है कि 1 से 15 अप्रैल के बीच किसी एक दिन बच्चों और एमसीडी में उनके टीचर्स को दिल्ली सरकार के स्कूल में विशेष रूप से बुलाया जाएगा और उनके लिए एक छोटी सी पार्टी आयोजित की जाएगी। अभी तक एमसीडी के 'फीडर स्कूलों' से 5वीं पास करके दिल्ली सरकार के 'लिंक स्कूलों' में 6वीं में एडमिशन पाने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को स्कूल के कई–कई बार चक्कर काटने पड़ते थे। सरकार ने फैसला किया है कि एमसीडी स्कूलों से डाटा लेकर पूरे एडमीशन प्रोसेस को ऑनलाइन कर लिया जाएगा। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एमसीडी के एजुकेशन डायरेक्टर्स से यह कहा है कि गर्मी की छुट्टियों में स्कूलों में समर कैंप का आयोजन करवाया जाए और 'चुनौती' प्लान के तहत बच्चों की पढ़ने की क्षमता को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। ■

समकालीन वैश्विक संकट के पीछे धर्म है या राजनीति?

-राम पुनियानी

वैश्विक स्तर पर 'इस्लामिक आतंकवाद' शब्द बहुप्रचलित हो गया है और इस्लाम के आंतरिक 'संकट' की कई तरह से विवेचना की जा रही है। कुछ लोगों की राय है कि इस्लाम एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है और इस संकट से निपटने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इतिहास गवाह है कि इसके पूर्व इस्लाम एक बहुत बड़े संकट से उबर चुका है। वह था क्रूसेड्स। वह एक बाहरी संकट था। इस्लाम का वर्तमान संकट उसका आंतरिक संकट है, जिसमें मुसलमान एक–दूसरे को ही मार रहे हैं। यहां तक कि एक ही पंथ के मुसलमान भी अपने साथियों का खून बहा रहे हैं। यह संकट पिछले कुछ दशकों में इस्लाम पर हावी हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि मुसलमान, स्वयं इस्लाम के सबसे बड़े शत्रु हैं और इस्लाम अब अपने ही अनुयायियों को निगल रहा है। कुछ लोगों ने मुस्लिम समाज की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में 'अच्छा मुसलमान, बुरा मुसलमान' शब्द ईजाद कर लिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस्लाम पर अतिवादियों ने कब्जा जमा लिया है। सुन्नी इस्लाम अतिवादी हो गया है और शिया इस्लाम का खोमैनीकरण हो गया है। यह तर्क भी दिया जा रहा है कि इस्लाम में अंदर से सुधार लाए जाने की जरूरत है।

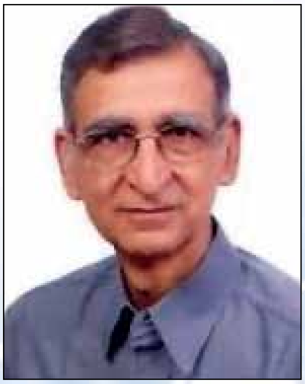

यह तर्क मध्यमार्गी मुसलमानों की व्यथा को प्रदर्शित करता है, जो अलकायदा से शुरू होकर आईएस और उसके कई अवतारों में फैल गया है। सच यह है कि यह विवेचना उथली है। जरूरत इस बात पर विचार करने की है कि इस्लाम से आतंकवाद के जुड़ाव की यह प्रक्रिया पिछले कुछ दशकों में ही क्यों शुरू हुई। यह मानना अनुचित होगा कि केवल इस्लाम के मानने वाले ही हिंसा करते हैं। साध्वी प्रज्ञा और गोडसे जैसे हिन्दू, असिन विराथू जैसे बौद्ध और एण्डर्स बर्लिन ब्रेविक जैसे ईसाई भी आतंकी हमलों में शामिल रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि आतंकवाद से जुड़े अधिकांश व्यक्ति मुसलमान हैं परंतु हमें यह समझना होगा कि कबजब राजनीति भी धर्म का भेस धर लेती है। और यह बात सभी धर्मों के बारे में सही है।

वर्तमान समय की बात करने से पहले हमें धर्मों की नैतिकता और उनके आदर्शों और धर्म के पहचान से जुड़े पहलुओं के बीच अंतर करना होगा। पहचान से जुड़े पहलुओं का सामाजिक दृष्टि से वर्चस्वशाली समूह, समाज पर अपना दबदबा कायम करने के लिए करते हैं। अधिकांश धर्मों के पुरोहित वर्ग ने सामाजिक दृष्टि से वर्चस्वशाली समूहों के साथ मिलकर सामाजिक ऊँचनीच को धार्मिक पवित्रता का चोला पहनाया। चर्च और मौलाना दोनों सामंती व्यवस्था के समर्थक रहे हैं और ब्राह्मणों ने जाति और लिंग पर आधारित पदक्रम को समाज पर लादा। यह सब समाज के श्रेष्ठी वर्ग द्वारा अपना राज कायम करने की कवायद का हिस्सा था।

हमें यह भी समझना होगा कि अलग–अलग समय पर विभिन्न राजाओं ने जिहाद, क्रूसेड्स और धर्मयुद्ध जैसे शब्दों का इस्तेमाल अपने साम्राज्यों को विस्तार देने के लिए किया। धर्म तो मात्र एक बहाना था, असल में वे सत्ता

के भूखे थे। सभी धर्मों के राजाओं के लक्ष्य एक से थे। उनका उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार करना नहीं वरन धर्म के नाम पर अपनी सत्ता को मजबूती और अपने साम्राज्य को विस्तार देना था। ऐसे में हम केवल जिहाद की बात कैसे कर सकते हैं? हम अन्य धर्मों के शासकों द्वारा धर्म के दुरूपयोग को कैसे भुला सकते हैं?

जहां तक भारत का संबंध है, 19वीं सदी में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय की प्रतिक्रिया स्वरूप अस्त होते जमींदारों और सामंतों के वर्ग ने अपनी उच्च सामाजिक स्थिति को बनाए रखने और जातिगत व लैंगिक पदक्रम को संरक्षित रखने के लिए धर्म की भाषा बोलनी शुरू कर दी। उदित होते राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध करने के लिए इस्लाम के नाम पर राजनीति करने के लिए मुस्लिम लीग जैसी संस्थाएं बनीं तो हिन्दू धर्म के नाम पर सत्ता का खेल खेलने के लिए हिन्दू महासभा और आरएसएस का गठन हुआ। एक ओर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद और गांधी जैसे लोग, जो भारतीय राष्ट्रवाद के पैरोकार थे तो दूसरी ओर थे जिन्ना, सावरकर, गोलवलकर और गोडसे जैसे व्यक्ति जो धार्मिक राष्ट्रवाद के हामी थे। गोडसे ने अपने समय के महानतम हिन्दू की हत्या की और उसके अनुसार ऐसा उसने 'हिन्दू समाज' की खातिर किया। बौद्ध धर्म के भेस में ऐसा ही राष्ट्रवाद म्यांमार और श्रीलंका में भी फलफूल रहा है।

पिछले कुछ दशकों में अमरीका, अपने साम्राज्यवादी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस्लाम का खलनायकीकरण करता आ रहा है। अमरीका का असली उद्देश्य कच्चे तेल के कुंओं पर कब्जा करना है। अपनी इसी लिप्सा के चलते अमरीका ने इस्लाम के अतिवादी संस्करण को प्रोत्साहन दिया। यह सर्वज्ञात है कि अमरीका ने पाकिस्तान के मदरसों में युवकों को इस्लाम के कट्टरवादी सऊदी संस्करण में प्रशिक्षित किया और उन्हें करोड़ों डॉलर और सैंकड़ों टन हथियार मुहैय्या करवाए। अमरीका तब इन युवकों के जरिए अफगानिस्तान से सोवियत संघ को बाहर करना चाहता था। बाद में ये लोग अमरीका के लिए ही भस्मासुर साबित हुए। इसके पहले अमरीका ने ईरान की प्रजातांत्रिक ढंग से निर्वाचित मोसाडिक सरकार को अपदस्थ किया था। इसके नतीजे में अंततः अयातुल्ला खोमैनी सत्ता में आए और इस्लामिक कट्टरता का बोलबाला बढ़ा। खोमैनी के सत्तासीन होने के बाद पश्चिमी मीडिया ने यह कहा था कि अब इस्लाम, दुनिया के लिए एक 'नया खतरा' बन गया है और 9/11 के आतंकी हमले के बाद, इसी मीडिया ने 'इस्लामिक आंतकवाद' शब्द गढ़ा।

ऐसा बताया जा रहा है मानो आतंकवाद के कैंसर का कारण इस्लाम है। परंतु गहराई से देखने पर हमें यह समझ आएगा कि हर धर्म में कई धाराएं होती हैं। कुछ प्रेम का प्रचार करती हैं तो कुछ नफरत फैलाती हैं। कबीर और निजामुद्दीन औलिया जैसे लोग गरीबों के साथ खड़े हुए और उन्होंने सत्ताधारी पुरोहित वर्ग का विरोध किया। पुरोहित वर्ग, धार्मिक पहचान का इस्तेमाल अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए करता आया है। गांधी भी हिन्दू थे और गोडसे भी। किसी धर्म की कौनसी धारा मजबूत होती है और कौनसी कमजोर, यह अक्सर तत्कालीन राजनैतिक शक्तियों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

यह सचमुच चिंता की बात है कि इस्लाम कई तरह की आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है परंतु यदि इस्लाम के अतिवादी पंथ शक्तिशाली बन गए हैं तो इसका कारण धर्म है या राजनीति। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गांधी के लिए हिन्दू धर्म समावेशी था तो गोडसे जैसों के लिए वह अन्यों से घृणा करना सिखाने वाला था। अतः, जरूरत इस बात की है कि हम धर्म का लबादा ओढ़े उस राजनीति को पहचानें, जो अतिवाद को बढ़ावा दे रही है और इस्लाम के मानवीय चेहरे को सामने नहीं आने दे रही है। हमारे समय में भी मौलाना वहीदउद्दीन और असगर अली इंजीनियर जैसी शख्सियतें हुईं जिन्होंने इस्लाम के मानवीय चेहरे को सामने रखा। परंतु सत्ता के समीकरण ाों के चलते, वे हाशिए पर पटक दिए गए और आईएस जैसी संस्थाएं केन्द्र में आ गईं। अब समय आ गया है कि हम यह समझें कि जो शक्तियां अतिवाद को प्रोत्साहन दे रही हैं वे दरअसल तेल के संसाधनों पर कब्जा करने के अपने लक्ष्य की प्राप्ति में संलग्न हैं। धर्म का आतंकवाद से कोई लेनादेना नहीं है।

(राम पुनियानी आईआईटी मुंबई के पूर्व प्रोफेसर और हमारे समय के महत्वपूर्ण विचारक हैं। लेख मूल रूप से अंग्रेजी में है जिसका हिन्दी रूपांतरण अमरीश हरदेनिया ने किया।) ■

डॉ. अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर पर विशेष

जातियाँ और उनका अस्तित्व ही राष्ट्र-विरोधी है-डॉ. अंबेडकर

डॉ अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में, 25 नवंबर, 1949 को, दिया गया भाषण आज पहले से अधिक प्रासंगिक हो चला है। डॉ अंबेडकर की यह बात हमें याद रखनी होगी, "हम राजनीतिक लोकतंत्र से ही संतुष्ट न हो जाएँ, हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी जरूर बनायें। जब तक राजनीतिक लोकतंत्र के आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो, सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र अधिक समय तक नहीं चल सकता"।

डॉ अंबेडकर ध्यान दिलाते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा दी गयी चेतावनी, जो मिल ने लोकतंत्र को सहेजने को इच्छुक, हर शख्स को दी थी। यानी अपनी स्वतंत्रता को किसी व्यक्ति के, चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो, चरणों में रखने से बचना या उस पर भरोसा करते हुए उसे ऐसी शक्तियां देना कि वह लोकतान्त्रिक संस्थाओं के लिए ही खतरा बन जाए, इस स्थिति से भी बचना. एक महान शख्सियत के प्रति कृतज्ञ होने में कोई बुराई नहीं है. पर डॉ आंबेडकर कहते हैं कि आखिर "कृतज्ञता की भी सीमाएं होती हैं".

डॉ अंबेडकर ने आयरिश देशभक्त पैट्रिक डैनियल ओ'कोनेल को उद्धृत करते हुए कहा कि सम्मान, प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हुआ जा सकता. यह चेतावनी दुनिया के किसी और देश के बरक्स भारत के लिए ज्यादा जरूरी है। भारत में भक्ति या नायक–पूजा ने, दुनिया के किसी और हिस्से के बरक्स, राजनीति में कहीं ज्यादे बड़ी भूमिका निभाई है. बतौर धर्म, भक्ति "आत्मा की मुक्ति की राह" भले हो सकती है. पर राजनीति में, भक्ति या नायक–पूजा, लोकतन्त्र के अवसान और अंततः तानाशाही की ओर ही ले जायेगी.

सामाजिक लोकतंत्र के मायने क्या हैं? इसका मतलब है ऐसी जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता व बंधुत्व को जीवन के सिद्धान्त के रूप में स्वीकार करती हो। स्वाधीनता, समानता व बंधुत्व के सिद्धांतों को, डॉ अंबेडकर के मत में, एक त्रिकोण के अलग–अलग हिस्सों के रूप में

नहीं देखा जा सकता। उनका मानना था कि स्वाधीनता, समानता व बंधुत्व आपस में इस तरह जुड़े होते हैं कि एक–दूसरे से अलग किए जाने पर, वे लोकतन्त्र के उद्देश्य को हासिल करने में ही बाधक बन जाएँगे।

हमें यह बात स्वीकार करनी होगी कि भारतीय समाज में दो चीजों की गैर–मौजूदगी है–समानता और बंधुत्व। डॉ अंबेडकर के मत में, सामाजिक धरातल पर देखें, तो भारतीय समाज "श्रेणीबद्ध असमानताओं का समाज" है। जहां कुछ लोगों के पास अथाह धन है, तो वहीं बहुत से लोग गरीबी में जीवन बिता रहे हैं।

इसी अंतर्विरोध पर टिप्पणी करते हुए डॉ अंबेडकर ने कहा कि "26 जनवरी 1950 के दिन हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में तो हमारे पास समानता होगी, पर सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। राजनीति में तो हम 'एक व्यक्ति एक वोट, एक वोट एक मूल्य' के सिद्धांत को स्वीकार कर लेंगे, पर सामाजिक और आर्थिक जीवन में, अपने सामाजिक और आर्थिक संरचनाओ के चलते, 'एक व्यक्ति एक मूल्य' के सिद्धांत को नकारते रहेंगे"।

डॉ संविधान सभा के सामने यह सवाल उठाते हैं कि "हम कब तक ऐसे अंतर्विरोधों के जीवन में जीते रहेंगे?" वे चेतावनी देते हुए कहते हैं कि 'अगर हमने ऐसा और अधिक समय तक किया, तो हम ऐसा अपने राजनीतिक लोकतंत्र की कीमत पर ही कर रहे होंगे। हमें इस अंतर्विरोध को जल्द से जल्द मिटाना होगा'।

दूसरी जिस चीज की कमी हमारे समाज में है, वह है बंधुत्व की भावना। बंधुत्व का मतलब बताते हुए डॉ अंबेडकर कहते हैं कि "यदि भारतीय लोग एकमेव हैं तो उनके बीच एक साझी भाई–चारे की भावना का होना। यह सिद्धान्त एका को बढ़ता है और सामाजिक जीवन को मजबूत करता है। पर इसे हासिल करना कठिन है"।

आगे डॉ अंबेडकर कहते हैं कि "मेरा मानना है कि 'हम एक राष्ट्र हैं' ऐसा मानकर हम एक बड़े भ्रम को बढ़ावा दे रहे हैं। हजारों जातियों में बंटे हुए लोग भला एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? जितनी जल्दी यह बात हम समझ लें कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अभी हम एक राष्ट्र नहीं हैं, उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा"।

दूसरा बनवास

राम बनवास से जब लौटकर घर में आये
याद जंगल बहुत आया जो नगर में आये
रक्से–दीवानगी आँगन में जो देखा होगा
छह दिसम्बर को श्रीराम ने सोचा होगा
इतने दीवाने कहां से मेरे घर में आये

धर्म क्या उनका है, क्या जात है ये जानता कौन
घर ना जलता तो उन्हें रात में पहचानता कौन
घर जलाने को मेरा, लोग जो घर में आये

शाकाहारी हैं मेरे दोस्त, तुम्हारे ख़ंजर
तुमने बाबर की तरफ़ फ़ेंके थे सारे पत्थर
है मेरे सर की ख़ता, ज़ख़्म जो सर में आये

पाँव सरयू में अभी राम ने धोये भी न थे
कि नजर आये वहाँ ख़ून के गहरे धब्बे
पाँव धोये बिना सरयू के किनारे से उठे
राम ये कहते हुए अपने दुआरे से उठे
राजधानी की फ़ज़ा आई नहीं रास मुझे
छह दिसम्बर को मिला दूसरा बनवास मुझे!

कैफ़ी आज़मी

बकौल डॉ अंबेडकर, यह सच्चाई स्वीकारने के बाद ही हम राष्ट्र बनने की जरूरत को बेहतर समझ पाएंगे और इस उद्देश्य को हासिल करने के तरीकों और साधनों के बारे में सोच पाएंगे। डॉ अंबेडकर इस बात से वाकिफ हैं कि इस उद्देश्य की प्राप्ति कठिन है क्योंकि सबसे पहले तो "जातियाँ और उनका अस्तित्व ही खुद में राष्ट्र–विरोधी हैं।"

इसका पहला कारण तो डॉ अंबेडकर ये बताते हैं कि जातियाँ सामाजिक जीवन में अलगाव को बढ़ावा देती हैं। दूसरे, वे एक जाति और दूसरी जाति के बीच ईर्ष्या और असहिष्णुता को बढाती हैं। अगर हम सच में राष्ट्र बनना चाहते हैं तो हमें इन सब मुश्किलों से पार पाना होगा। क्योंकि डॉ अंबेडकर के शब्दों में कहें तो "बंधुत्व यथार्थ तभी हो सकता है जब राष्ट्र मौजूद हो। और बगैर बंधुत्व के समानता और स्वाधीनता महज दिखावा होंगी"।

शुभनीत कौसिक

वह अनुपम आदमी !

प्रख्यात गाँधीवादी पर्यावरणविद् अनुपम मिश्र नहीं रहे। 19 दिसंबर की सुबह दिल्ली के एम्स में उनका निधन हो गया जहाँ वे कैंसर के इलाज के लिए भर्ती थे। 'आज भी खरे हैं तालाब' और 'राजस्थान की रजत बूँदें' जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखक अनुपम मिश्र अपनी सादगी और समर्पण के लिए मशहूर थे। मशहूर पत्रकार और संपादक, स्व.प्रभाष जोशी ने उन पर 1993 में 'अपने पर्यावरण का यह अनुपम आदमी' शीर्षक से एक लेख लिख कर उनके महत्व को रेखाँकित किया था। प्रस्तुत है उसका संपादित रूप——

ये कागज मैं उन्हीं अनुपम मिश्र और उनके काम पर काले कर रहा हूं जिनका जिक्र आपने इस जगह पर कई बार देखा और पढ़ा होगा। खतरा है कि आप में से कई लोग मुझ पर पक्षपात करने यानी अपने ही लोगों में रेवड़ी बांटने जैसा अंधत्व होने का आरोप लगा सकते हैं। लेकिन इसलिए कि आप पर कोई आरोप लगा सकता है, आप वह करना और कहना छोड़ दें जो आप को करने और कहने को प्रेरित कर रहा है तो आपके होने–करने का मतलब क्या रह जाएगा?

मन में कहीं बैठा था कि अनुपम से मुठभेड़ सन इकहत्तर में हुई। लेकिन यह गलत है। गांधी शताब्दी समिति की प्रकाशन सलाहकार समिति का काम संभालने के बाद देवेंद्र भाई यानी राष्ट्रीय समिति के संगठन मंत्री ने कहा कि भवानी भाई ने गांधी पर बहुत सी कविताएं लिखी हैं, वे उनसे लो और प्रकाशित करो। उन्हें लेने की जुगाड़ में ही भवानी मिश्र के घर जाना हुआ और वहीं उनके तीसरे बेटे यानी माननीय अनुपम प्रसाद मिश्र, अनुपम मिश्र या पमपम से मिलना हुआ। भवानी भाई की ये कविताएं गांधी पंचशती के

नाम से छपी–पांच सौ से ज्यादा कविताएं हैं। सर्वोदयी गतिविधियों का दिल्ली में केंद्र गांधी शांति प्रतिष्ठान हो गया और अनुपम और मैं–आंदोलन के बारे में लिखने, पत्रिकाएं निकालने और सर्वोदय प्रेस सर्विस चलाने में लग गए. उसी सिलसिले में अनुपम का उत्तराखंड आना–जाना होता. भवानी बाबू गांधी निधि में ही रहने आ गए थे, इसलिए कामकाज दिन–रात हो सकता था. फिर चमौली में चंडीप्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने चिपको कर दिया. चिपको आंदोलन पर पहली रपट अनुपम मिश्र ने ही लिखी और चूंकि सर्वोदयी पत्रिकाओं की पहुंच सीमित थी इसलिए वह रपट हमने रघुवीर सहाय को दी और दिनमान में उन्होंने उसे अच्छी तरह छापा.

पिछले तीन साल से होशंगाबाद में नर्मदा किनारे उसके लिए पर्यावरण की कोई संस्था खड़ी करने के जुगाड़ में हूं. इसलिए भी देश के पर्यावरण के लिए नर्मदा योजना आरपार की साबित हो सकती हैं. लेकिन अनुपम को सरकारी जमीन और पैसा नहीं चाहिए. विदेशी पैसे को वह हाथ नहीं लगाएगा. और तो और गांधी शांति प्रतिष्ठान छोड़कर अपना बनाया गांधी शांति केंद्र चला रहे राधाकृष्ण ाजी से भी वह संस्था खड़ी करने के लिए एकमुश्त पैसा नहीं लेगा. कुछ उद्योगपतियों से पैसा ला सकता हूं लेकिन मुझे मालूम है कि वे पैसा क्यों और कैसे देते हैं. और वह लाना अनुपम के साथ छल करना होगा.

पर्यावरण का काम आजकल विदेश यात्रा का सबसे सुलभ मार्ग है. अनुपम एकाध बार तो नैरोबी गया क्योंकि वहां पर्यावरण संपर्क केंद्र के बोर्ड में निदेशक बना दिया गया था. कुछ और यात्राएं वैसे ही की जैसे आप हम मेरठ या अलवर या चड़ीगढ़ हो आते हैं. झोला टांगा और हो आए. मैं नहीं जानता कि बाहर बैठक में अंग्रेजी कैसे बोलता होता? बोलना

ही नहीं चाहता. मुंह टेढ़ा कर अमेरिकी स्लैंग में अंग्रेजी बोलना तो अनुपम के लिए पापकर्म होगा. धीरे–धीरे उसने बहुत जरूरी विदेश यात्राएं भी बंद कर दीं.

इस साल (1993) रियो में हुए विश्व सम्मलेन का कार्यक्रम तय करने के लिए पिछले साल फ्रांस सरकार की मदद से पर्यावरण संपर्क केंद्र ने पेरिस में सम्मलेन किया था. अनुपम को ही लोग भेजने थे. उसने भेजे पर खुद ऐन मौके पर ना कर गया. रियो भी नहीं गया. भारत सरकार या राज्य सरकारों को पर्यावरण पर सलाह वह नहीं देता. कमेटियों और प्रतिनिधिमंडलों में शामिल नहीं होता. गांधी शांति प्रतिष्ठान में चुपचाप सर गड़ाए मनोयोग से काम करता रहता है. उसकी पुरानी कुर्सी के पीछे एक स्टिकर चिपका है 'पॉवर विदाउट परपज' सत्ता बिना प्रयोजन के. अनुपम के पास प्रयोजन ही है सत्ता का तो स्पर्श भी नहीं है. अभी तक वैसे ही तंगी में यात्रा करता है. जैसी हम जेपी आंदोलन के समय झोला लटकाए किया करते थे. और ज्यादातर यात्राएं बीहड़ सुनसान या रेगिस्तान या जंगलों में.

'देश का पर्यावरण' उस ने कोई नौ साल पहले निकाली. संपादित है. लेकिन क्या जानकारी, क्या भाषा, क्या सज्जा और क्या सफाई. जिस दिलीप चिंचालकर ने जनसत्ता का मास्टहेड बनाया, अखबार डिजाइन किया उसी दिलीप ने इस किताब का ले आउट स्केचिंग और सज्जा की है. हिंदी में ही नहीं, इस देश में अंग्रेजी में भी ऐसी किताब निकली हो तो बताना. लेकिन अनुपम ने किताब निकालने में भी शांति प्रतिष्ठान का पैसा नहीं लगाया. फोल्डर छपाया. संस्थाओं और पर्यावरण में रुचि रखने वाले लोगों से अग्रिम कीमत मंगवाई. उसी से कागज खरीदा, छपाई करवाई. फिर खुद ही चिट्ठी लिख–लिखकर किताब बेची. दो हजार छपवाई थी. साठ हजार लागत लगी. दो लाख कमाकर अनुपम ने प्रतिष्ठान में जमा करवा दिए. चार साल बाद 'हमारा पर्यावरण' निकाली, देश के पर्यावरण से भी बेहतर. इसका भी फोल्डर छपवाकर अग्रिम कीमत इकट्ठी की. इस बार डेढ़ लाख के आसपास आई. छह हजार छपवाई. बिना किसी मदद से खुद चिट्ठियां लिखकर बेचीं. शांति प्रतिष्ठान को कमाकर दिए नौ लाख रुपये.

अब ये दोनों किताबें दुर्लभ हो गई हैं. पर्यावरण मंत्री कमलनाथ को किसी को भेंट करने के लिए चाहिए थी. उनके दफ्तर ने बहुत फोन किए, मुश्किल से दो प्रतियां जुटीं. और मजा यह है कि पर्यावरण मंत्रालय ने इन पुस्तकों को नहीं खरीदा. हिंदी के किसी भी राज्य ने किताबों की सरकारी खरीद में इसे नहीं लिया. किसी प्रकाशक ने वितरण और बिक्री में कोई मदद नहीं की. पिछले दस साल के देश के पर्यावरण पर हिंदी में ऐसी किताबें नहीं निकली. अनुपम ने न सिर्फ लिखी और छापीं, बेची भी और कोई दस लाख कमाकर संस्था को दिया. हिंदी के किसी प्रकाशक को चुल्लूभर पानी चाहिए तो पर्यावरण की ये दो पुस्तकें दे सकती हैं.

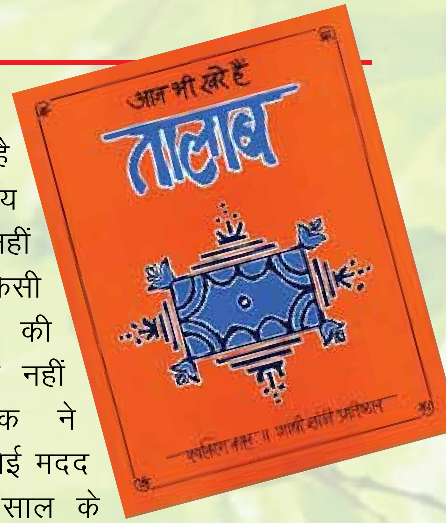

और अब अनुपम मिश्र ने 'आज भी खरे हैं – तालाब'– निकाली है. यह संपादित नहीं है. सीधे अनुपम ने लिखी है। नाम कहीं अंदर है छोटा सा. लेकिन हिंदी के चोटी के विद्वान ऐसी सीधी, सरल, आत्मीय और हर वाक्य में एक बात कहने वाली हिंदी तो जरा लिखकर बताएं. जानकारी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं. अनुपम ने तालाब को भारतीय समाज में रखकर देखा है. सम्मान से समझा है. अद्भुत जानकारी इकट्ठी की है और उसे मोतियों की तरह पिरोया है. कोई भारतीय ही तालाब के बारे में ऐसी किताब लिख सकता था. लेकिन भारतीय इंजीनियर नहीं, पर्यावरणविद नहीं, शोधक विद्वान नहीं – भारत के समाज और तालाब से उस के संबंध को सम्मान से समझने वाला विनम्र भारतीय.

ऐसी सामग्री हिंदी में ही नहीं अंग्रेजी और किसी भी भारतीय भाषा में आप को तालाब पर नहीं मिलेगी. तालाब पानी का इंतजाम करने का पुण्यकर्म है तो इस देश के सभी लोगों ने किया है. उनको, उनके ज्ञान को और उनके समर्पण को बता सकने वाली एक यही किताब है. आप चाहें तो कलकत्ते के राष्ट्रीय ग्रंथागार देख लें. यह किताब भी इसी तरह निकाली है. तीन हजार छपवाई थीं. तीन महीने में दो हजार एक सौ बेच दी हैं. कोई डेढ़ लाख कमाकर जमा करवा दिया है. वृक्ष मित्र पुरस्कार जिस साल चला अनुपम को दिया गया था. पर्यावरण का अनुपम, अनुपम मिश्र है. उस के जैसे व्यक्ति की पुण्याई पर हमारे जैसे लोग जी रहे हैं. यह उसका और हमारा –दोनों का सौभाग्य है. ■

हिंदी अकादमी की राष्ट्रीय संगोष्ठी

आज़ादी की नई उड़ान है स्त्री लेखन!

हिंदी साहित्य सृजन में स्त्रियों की भूमिका' विषय पर आधारित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी (16–17 नवम्बर 2016) में कथा साहित्या में नई धज के साथ खड़ी हो रही स्त्री की भूमिका पर गंभीर चर्चा ही। कहा गया कि स्त्री को गुलामी का अहसास हो गया है और अब वह आजाद होकर रहेगी।

पहले सत्र में सुश्री प्रियंका सोनकर ने चर्चा शुरू करते हुए कहा–''मैं स्त्री चेतना की ऊर्जा गौतम बुद्ध के अप्प दीपो भव, सावित्री बाई फुले के ज्ञान अर्जित करो, डॉ अम्बेडकर के शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, तथा गुलाम को अगर गुलामी का अहसास करो दो तो वो मुक्त हो उठेगा, से मानती हूँ। अगर किसी स्त्री में ये समझ नहीं है तो वो कभी भी चेतनाशील नहीं हो सकती।

कथाकार मनीषा कुलश्रेष्ठ ने अपने पर्चे से विषय पर अपनी बात रखते हुए, कहा–''जब हम उपन्यास में नारी चेतना की बात करें तो मुझे लगता है कि हम खुद से यह सवाल जरूर करें कि चेतना अगर है तो क्या वह प्रवाहमान है? क्या यह चेतना उस छोर तक पहुंच रही है जहाँ एक यंत्रणा पाती स्त्री सुबकती है रसोई के मटमैले धुंए में। या विवाह में दिनरात बलत्कृत होती है। आज के संक्रमण काल में जहाँ एक ओर भरापूरा स्त्रीवाद चमक रहा है, शहर की पढ़ी लिखी महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर सजग सशक्त हैं। वहीं इसी भारतीय समाज की कई कई आर्थिक सामाजिक तहों के भीतर बाहर स्त्रियां आज भी शोषित, अपमानित, बलत्कृत और प्रताड़ित हो रही हैं। पुरातन कुरीतियों की शिकार हैं। उन्हें पता ही नहीं इस धरती पर उनके हिस्से कोई अधिकार हो भी सकते हैं। या कहीं कोई वुमन सैल है जो उनकी शिकायत सुन सकती है।

कथाकार इंदिरा दांगी के पर्चे का शीर्षक था–'हिंदी उपन्यास और स्त्री चेतना'। उन्होंने 'चित्रलेखा', 'सेवासदन' से लेकर 'आवां', 'चाक' और 'अल्मा कबूतरी' तक अनेक उपन्यासों और कथाकारों का उल्लेख करते हुए स्त्री–चेतना के आयामों को स्पष्ट किया। अंत में अपने उपन्यासों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा–''हम नए हैं हमारे पाठकों का नया होना प्रतीक्षित है।''

सुश्री उमा ने एक कहानी की शक्ल में अपना पर्चा प्रस्तुत किया। इस रचनात्मक पर्चे में हिंदी के बहुचर्चित उपन्यासों की नायिकाएं एक साथ मिलकर स्त्री–चेतना पर अपनी बात कहती हैं। मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा, मनीषा कुलश्रेष्ठ आदि के स्त्री पात्रों को सामने रखते हुए अपनी बात कहीं। इसी तरह डॉ. स्वाति श्वेता ने भी अपने पर्चे में हिंदी की उपन्यास यात्रा के अनेक उपन्यासों को सामने लाकर विषय संबंधी अनेक गंभीर पक्षों का विवेचन किया।

सत्र के अंत में वरिष्ठ कथाकार मृदुला गर्ग ने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में कहा–''पुरूष चेतना और स्त्री चेतना में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। संकट और आपदा दोनों पर समान पड़ती है और उसका सामना भी दोनों को करना पड़ता। सत्र का संचालन जामिया विवि के हिंदी विभाग से जुड़े डॉ. रहमान मुस्सविर ने किया।

दूसरे सत्र का विषय था–'कहानी में स्त्री छवियां'। चर्चा में भाग लेते हुए डॉ.बलवंत कौर ने कहा कि पितृसत्ता ने अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए स्त्रियों के स्टीरियोटाइप को गढ़ा है। स्त्री विमर्श का एक बड़ा हिस्सा इन गढ़ी हुई छवियों और मिथकों को ध्वस्त करता है क्योंकि स्त्रियां जानती हैं लिखने से लिखना ही नहीं जीना भी आता है।

कथाकार–आलोचक प्रज्ञा ने अपने वक्तव्य में सन् 2000 के बाद से अब तक की हिंदी कहानी को आधार बनाते हुए आज की हिंदी कहानी में कई स्त्री छवियों से साक्षात्कार कराया

जो अपने साधारण से जीवन में अपनी सोच और कर्मशक्ति से वैशिष्ट्य प्राप्त कर लेती हैं। शिक्षा, जाति, धर्म, अर्थ में पिछड़ी हुई औरतें अचानक किस तरह जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेती हैं, ऐसी कई छवियां उन्होंने हिंदी कहानी के माध्यम से स्पष्ट कीं।

कवि और आलोचक विपिन चौधरी ने साठ–सत्तर के दशक में कामकाजी स्त्रियों की छवि की चर्चा के साथ वैचारिक दृढ़ता आने के बाद हिंदी कहानी में स्त्री पात्रों द्वारा मन की लगाम को ढीला छोड़ने की बात कहीं। उसे किसी चोर दरवाजे की जरूरत नहीं थी उसने मेन गेट से प्रवेश किया। उन्होंने कहा कि इक्कीसवीं सदी की स्त्री अपनी मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी के कारण हर बार अलग–अलग रूप में दिखाई देती है।

सुश्री रजनी मोरवाल का कहना था कि समय–समय पर स्त्री पात्रों की छवियां बदलने का काम कई कथाकारों ने किया। नई तकनीक और सोच ने आधुनिक स्त्री छवि का गठन किया। अनेक पीढ़ियों के अनेक कथाकारों की कहानियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि समाज में जो घट रहा है उसका बेबाक मूल्यांकन होना चाहिए। स्त्री की पैसिव नहीं एक्टिव छवि सामने उभरनी चाहिए।

कहानी में दलित स्त्री की भिन्न छवियों को डॉ. सुमित्रा मेहरोल ने अपने पर्चे में व्यक्त किया। उन्होंने समकालीन दलित कहानियों के उदाहरणों से स्पष्ट किया कि आज की दलित स्त्री जड़ जातिवाद और पितृसत्ता के विरुद्ध अपनी लड़ाई जमकर लड़ रही है।

अध्यक्षीय वक्तव्य में कथाकार सुधा अरोड़ा ने विशेषकर स्त्री लेखन को देह तक सीमित रहने के खतरे और स्त्री लेखन से दूर हो रहे अन्य जनसरोकारों के खतरे को उजागर किया। उन्होंने माना कि स्त्री लेखन में सावधानी बरतने का समय है। इधर सोफ्ट पोर्न भी स्त्री कहानी में चला आया है। सुधा अरोड़ा का साफ कहना था कि या तो विशुद्ध पोर्न लिखें या जनसरोकारों पर लिखें ये सोफ्ट पोर्न का रंग कहानी में न घोला जाए। सत्र का संचालन कहकशां अहसान साद ने किया।

तीसरे सत्र का विषय था–'पितृसत्ता का विद्रूप और स्त्री की कलम'। चर्चा में भाग लेते हुए डॉ. सुधा सिंह ने कहा कि पितृसत्ता के अंदर जो धारणा वैचारिक आधारभूमि का काम करती है, वह यह है कि ईश्वर ने स्त्री और पुरुष अलग अलग बनाए हैं, दोनों के काम अलग हैं, दोनों की शारीरिक बनावट ही नहीं सामाजिक भूमिका में भी अंतर है और यह अंतर रहेगा। इसी निर्धारणवादी धारणा के तहत स्त्री और उसकी सामाजिक भूमिका को हेय तथा पुरुष और उसकी सामाजिक भूमिका को श्रेष्ठ बनाया जाता है। इस पूरी वैचारिक समझ और सामाजिक व्यवहार को अमली जामा पहनाने के लिए तमाम संस्थाओं का सहारा लिया जाता है। निजी और सार्वजनिक का अंतर किया जाता है। भाषा इसमें एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भाषा की दुनिया में स्त्री सहयोगी नहीं, घुसपैठिया है। चेतस् स्त्री के अनुभव और उपलब्ध ज्ञान में भयानक द्वन्द्व चलता है। जब भी स्त्री लिखती है, वह इस द्वन्द्व से गुजरती है।

अनुवादक सुश्री अमृता बेरा ने बांगला साहित्य में स्त्री की उपस्थिति, उसके संघर्ष और उसके प्रतिकार की छवियों को उद्घाटित किया। डॉ. कौशल पंवार ने दलित स्त्री और साहित्य में स्त्री की भूमिका पर अपनी बात रखते हुए अनेक कहानियों के जरिए पितृसत्ता के विद्रूप के विरोध में उठती कहानियों का हवाला दिया। समाजविज्ञानी सुश्री इंदु अग्निहोत्री ने कहा कि पितृसत्ता निरंतर अपना स्वरूप बदल रही है। उन्होंने भारतीय समाज में पितृसत्ता की गहरी जड़ों का उल्लेख करते हुए बताया कि संबंधों तक में मातृपक्ष के सम्बोधनों की उपेक्षा की जाती है। लोकाचारों में स्त्री की उपेक्षा के कई आयामों को उन्होंने प्रस्तुत किया।

पत्रकार मनीषा ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज भी स्त्री पत्रकार को पोडियम तक पहुंचने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने अपने पत्रकार जीवन के सघर्षों को भी साझा किया। अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में डॉ. रमा ने सभी वक्ताओं के वक्तव्यों पर सुचिंतित टिप्पणी करते हुए कहा–''मेरा व्यक्तिगत मानना है कि दुनिया का कोई भी विमर्श अतिवादी होकर नहीं किया जा सकता। अतिवादी होकर हम 'कोट' करने लायक तो बोल देते हैं लेकिन उसके भाव, यथार्थ जीवन के सरोकारों से कट जाते हैं। भारत में स्त्रियां सैकड़ों वर्गों में विभाजित हैं उनमें से नब्बे प्रतिशत स्त्रियों को देह का विमर्श बेईमानी लगता है क्योंकि उनके यहां पेट सबसे बड़ा सवाल है। पुरूषों को कठघरे में खड़ा करके स्त्रियों को मुक्ति नहीं मिल सकती क्योंकि वे भी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं।

जामिया मिलिया इस्लामिया के हिंदी विभाग की अध्यक्ष और कथाकार हेमलता माहिश्वर ने कार्यक्रम की सार्थकता पर चर्चा की। साथ ही सभी वक्ताओं, हिंदी अकादमी और विशेष रूप से अकादमी अध्यक्ष मैत्रेयी पुष्पा का इस कार्यक्रम के लिए आभार प्रकट किया। इस सत्र का संचालन डॉ. इंदु वीरेंद्र ने किया ■

पृथ्वीराज का 'दिल्ली सूत्र'

–नलिन चौहान

"हम बेशक आसमान में उड़ रहे हो पर हमारा जमीन से नाता नहीं टूटना चाहिए। पर अगर हम अर्थशास्त्र और राजनीति की जरूरत से ज्यादा पढ़ाई करते हैं तो जमीन से हमारा नाता टूटने लग जाता है। हमारी आत्मा प्यासी होकर तन्हा हो जाती है। हमारे राजनीतिक मित्रों को उसी प्यासी आत्मा की स्थिति से रक्षित रखने और बचाने की जरूरत है और इस उद्देश्य के लिए शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, कवियों, लेखकों और कलाकारों के रूप में नामित सदस्य यहाँ (राज्यसभा में) उपस्थित हैं''

यह राज्यसभा में फिल्मों और थियेटर के दिग्गज पृथ्वीराज कपूर के भाषण का एक अंश है। उन्होंने इस बेहतरीन व्याख्या के जरिये राज्यसभा में कलाकार के रूप में नामित सदस्यों की भूमिका को स्पष्ट किया। यह साबित हुआ कि संसद के उच्च सदन में उनका नामांकन कितना उचित था। प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू पृथ्वीराज के बड़े प्रशंसक थे। पृथ्वीराज को वे दो बार, वर्ष 1952 में दो साल के लिए और फिर वर्ष 1954 में पूर्ण काल के लिए राज्यसभा का सदस्य नामित किया गया। पुस्तक थिएटर के सरताज पृथ्वीराज'' (प्रकाशकः राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय) में योगराज लिखते हैं कि पृथ्वीराज राज्यसभा में अपने नामांकन को लेकर दुविधा में थे। बकौलपृथ्वीराज, "थिएटर की भलाई और राज्यसभा की व्यस्तताएं, पर क्या किया जाए! मुझे इन परिस्थितियों का मुकाबला तो करना होगा। थिएटर को भी जिंदा रखना है और सरकार के इस सम्मान को भी निभाना है। दूसरा कोई चारा नहीं है चलो थिएटर की सलामती के लिए और बेहतर लड़ाई लड़नी होगी।''

"राज्य सभा के नामांकित सदस्य पुस्तिका'' (प्रकाशक–राज्यसभा सचिवालय) के अनुसार, पृथ्वीराज कपूर ने

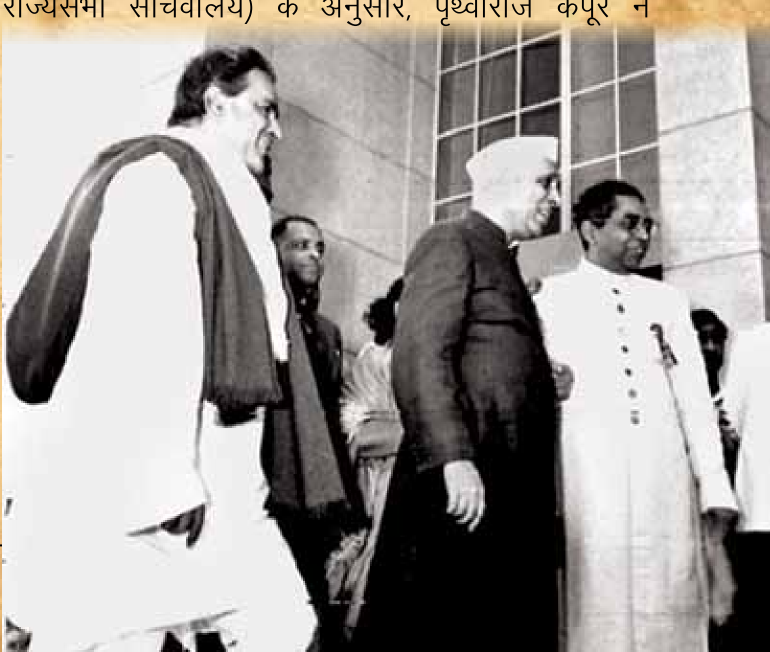

सदन के पटल पर नामजद सदस्यों (जिसका संदर्भ मैथिलीशरण गुप्त का था) के अपने आकाओं के विचारों को व्यक्त करने के आरोप का खंडन करते हुए कहा, "जब यहां अंग्रेजों का राज था और जनता पर दमिश्क की तलवार लटक रही थी तब मैथिलीशरण गुप्त जैसे क्रांतिकारी थे, जिनमें भारत भारती लिखने का साहस था। ऐसे में, उस समय हिम्मत करने वाले निश्चित रूप से आज अपने मालिकों के समक्ष नहीं नत मस्तक होंगे। वे (नामजद सदस्य) तर्क और प्रेम के सामने झुकेंगे और न कि किसी और के सामने।" पृथ्वीराज कपूर ने देश की सांस्कृतिक एकता के अनिवार्य तत्व को रेखांकित करते हुए 15 जुलाई 1952 को राज्यसभा में एक राष्ट्रीय थिएटर के गठन का सुझाव दिया था। जिसके माध्यम से विभिन्न संप्रदायों और भिन्न–भिन्न भाषाएं बोलने वाले व्यक्तियों को एक साथ लाने और एक समान मंच साझा करने तथा उचित व्यवहार सीखने के अवसर प्रदान किए जा सकें।

वर्ष 1954 में संगीत नाटक अकादमी के 'रत्न सदस्यता सम्मान' से सम्मानित होने के बावजूद उन्होंने पृथ्वी थिएटर के लिए किसी भी तरह की सरकारी सहायता लेने से इंकार कर दिया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उन्हें कई सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों में विदेश भेजा। पृथ्वीराज कपूर और बलराज साहनी वर्ष 1956 में चीन की यात्रा पर गए एक भारतीय सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे।

रंगमंच का कलाकार होने और फर्श से अर्श तक पहुँचने के कारण वे रंगमंच की चुनौतियों और कलाकारों को रोजमर्रा के जीवन में होने समस्याओं से अच्छी तरह से परिचित

थे। उन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मंचीय कलाकारों के कामकाज की स्थिति को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की। इसी का नतीजा था कि वे मंचीय लाकारों के लिए रेल किराए में 75 प्रतिशत की रियायत प्राप्त करने में सफल रहे। उनकी पोती और पृथ्वी थिएटर को दोबारा सँभालने वाली संजना कपूर के अनुसार, "मेरे दादा के कारण ही आज हम 25 प्रतिशत रेल किराए में पूरे देश भर में यात्रा करने में सक्षम हैं अन्यथा हम अपना अस्तित्व ही नहीं बचा पाते।" इतना ही नहीं, पृथ्वीराज ने देश के अनेक शहरों में रवींद्र नाट्य मंदिरों की भी स्थापना की।

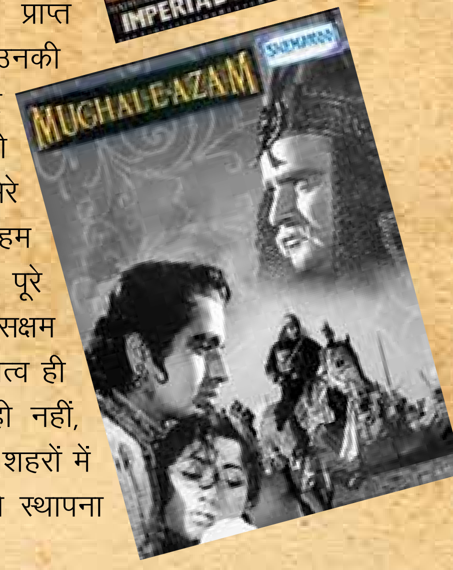

थिएटर में रूझान के कारण कानून की अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर पेशावर से मुंबई अपनी किस्मत आजमाने पहुंचे और पृथ्वीराज इंपीरियल फिल्म कंपनी से जुड़े। वर्ष 1931 में प्रदर्शित पहली भारतीय बोलती फिल्म 'आलमआरा' में पृथ्वीराज ने बतौर सहायक अभिनेता काम करते हुए चौबीस वर्ष की आयु में ही अलग–अलग आठ दाढ़ियां लगाकर जवानी से बुढ़ापे तक की भूमिका निभाई। फिर राज रानी (1933), सीता (1934), मंजिल (1936), प्रेसिडेंट, विद्यापति (1937), पागल (1940) के बाद पृथ्वीराज फिल्म सिकंदर (1941) की सफलता के बाद कामयाबी के शिखर पर पहुंच गए। उनकी अंतिम फिल्मों में राज कपूर की 'आवारा' (1951), 'कल आज और कल', जिसमें कपूर परिवार की तीन पीढियों ने अभिनय किया था और ख्वाजा अहमद अब्बास की 'आसमान महल' थी। उन्होंने कुल नौ मूक और 43 बोलती फिल्मों में काम किया।

हिंदी सिनेमा के सितारे पृथ्वीराज कपूर ने कनॉट प्लेस के सिनेमाघरों में कई नाटकों का प्रदर्शन किया। पुस्तक

Regal in 50s

Regal now

थिएटर के सरताज पृथ्वीराज के अनुसार, "इसी बीच पृथ्वीराज कपूर अपना थिएटर लेकर दिल्ली आए। उन दिनों उनके तीन नाटक बहुत चर्चित थे–"शकुन्तला", "दीवार" और "पठान"। ये तीनों नाटक अपनी–अपनी जगह लोगों की खूब वाह–वाही ले रहे थे। संस्कृत भाषा के महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुन्तलम् उर्दू में बिलकुल पारसी थिएटर की शैली में नाटकीय रूपांतर था। दूसरा नाटक "दीवार" था जो राष्ट्रीय एकता पर देश के विभाजन के विरोध में था। इसी तरह पृथ्वी थिएटर के तीसरे नाटक "पठान"को लिखने में भी पृथ्वीराज का बड़ा हाथ था।

'आई गो साउथ विथ पृथ्वीराज एंड हिज पृथ्वी थिएटर्स' पुस्तक (प्रकाशकरू पृथ्वी थिएटर्स) में प्रोफेसर जय दयाल लिखते हैं, 'पृथ्वी ने हर तरह के उतार–चढ़ाव का सामना करते हुए निर्भीकता के साथ 'दीवार' का मंचन किया। एक लम्बे अंतराल के बाद इस नाटक को आला स्तर के नेताओं से एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति के रूप में मान्यता मिली। तत्कालीन उपप्रधानमंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नाटक को अंत तक बैठकर देखा जबकि वह केवल मात्र एक सरकारी उपस्थिति की खानापूर्ति के लिए आए थे। दीवार ने उन्हें गुदगुदाने के साथ उनकी आँखे भी नम कर दी और इसका नतीजा पृथ्वी थिएटर को मनोरंजन कर से मिली छूट के रूप में सामने आया।

गौरतलब है कि पहले कनाट प्लेस के रीगल सिनेमा में रूसी बैले, उर्दू नाटक और मूक फिल्में दिखाई जाती थीं। पृथ्वीराज कपूर ने कनॉट प्लेस के कई थिएटरों में मंचित अनेक नाटकों में अभिनय किया था। आजादी से पूर्व उस दौर में, यहां समाज के उच्च वर्ग का तबका, जिनमें अंग्रेज अधिकारी और भारतीय रजवाड़ों के परिवार हुआ करते थे, नाट्य प्रस्तुति देखने आया करता था।

उस समय जब दिल्ली में पृथ्वी थिएटर के नाटक रीगल सिनेमा हाल में हो रहे थे। सारे शो हाउसफुल थे। लोग टूटे पड़ते थे। हो सकता है, लोगों की इस भीड़ का कारण बहुत हद तक ये हो कि स्टेज पर उनके सामने एक बहुत बड़ा नामवर फिल्मी अभिनेता चलता–फिरता नजर आएगा। इसके अतिरिक्त लोग देखेंगे तो नाटक ही न। योगराज के शब्दों में, जहां तक मुझे याद है, दो या तीन सप्ताह पृथ्वी थिएटर अपने इन तीनों नाटकों को बार–बार खेलते रहे और लोग इसी तरह भीड़ की शक्ल में आते रहे।"

हिंदी फिल्मों में सम्मोहित अभिनय और रंगमंच को नई दिशा देने वाले पृथ्वीराज का 29 मई, 1972 को निधन हुआ। उन्हें मरणोपरांत भारतीय सिने जगत के सबसे बड़े सम्मान यानी 'दादा साहब फाल्के सम्मान' से सम्मानित किया गया।

निर्भया सदाः सेंट्रल पार्क में 'ए वूमन अलोन' का मंचन

एक स्त्री के विलाप में गूँजा सदियों का ज़ुल्म!

सत्तर के दशक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित इटली के महान नाटककार दारियो फो और फ्रांका रामे ने मिलकर एक नाटक लिखा था–ए वूमन अलोन यानी एक अकेली स्त्री। इस नाटक में एक स्त्री है जिसका पति उसे घर में बंद करके चला गया है और वह एकालाप के जरिये अपने जीवन के सुख–दुख का बयान करती है। 16 दिसंबर की शाम निर्भया की याद में यह नाटक कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में खेला गया और समाज के दोमुँहेपन और स्त्री को मनुष्य से एक दर्जा नीचे समझने की उसकी सदियों पुरानी समझ को बेपर्दा कर गया।

यूँ तो निर्भया काँड की बरसी पर दिल्ली में तमाम कार्यक्रम हुए लेकिन दिल्ली सरकार का यह 'निर्भया सदा' इस अर्थ में विशिष्ट था कि इसमें स्त्रियों के उत्पीड़न के नाम पर पुराने नारे नहीं दोहराये गए बल्कि स्त्रियों के मन में झाँकने का प्रयास किया गया और स्त्री के नजरिये से असमानता को देखा गया।

सेंट्रल पार्क में अस्मिता थिएटर ग्रुप की ओर से प्रस्तुत इस नाटक का निर्देशन किया था अरविंद गौड़ ने और अभिनय था शिल्पी मारवाह का। चुस्त निर्देशन और दुरुस्त अभिनय का ही असर था कि रिश्तों के तनाव में उलझी स्त्री मन की परतें उघड़ने के साथ दर्शक सिहर रहे थे। हर रिश्ते की आड़ में स्त्री के शिकार होने की यह कथा वह आईना है जिसमें लैंगिक असमानता ही नहीं स्त्री शोषण को परंपरा बना देने वालों का बदसूरत चेहरा उभरता है। नाटक का अंत एक विलाप से हुआ जिसने समाज को बदलने और महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने की चुनौती पेश की जिसके बिना मनुष्यता की यात्रा पूर नहीं होती।

नाटक के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के संक्षिप्त भाषण ने दर्शकों के विचारतंत्र को झकझोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था की लैंगिक असमानता की बुनियाद डालती है जिसमें सीता हमेशा रसोई में काम करती है और राम बाजार जाता है। परीकथाओं में भी एक सुंदर राजकुमारी के शापग्रस्त हो असुंदर होने और फिर परी के आशीर्वाद से सुंदर होने का किस्सा दोहराया जाता है और समाज बाजार के मानदंडों के अनुरूप सुंदर बनने की होड़ में फँस जाता है। दिल्ली के संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि देश में कानून बहुत हैं,लेकिन हमें लोगों को जागरूक करना है। कार्यक्रम में निर्भया के माता–पिता भी उपस्थित थे। ■

संक्षेप में...

1 किमी दायरे के हर बच्चे का एडमीशन

नर्सरी ऐडमिशन को लेकर हर साल होने वाली रही अफरातफरी को ख़त्म करने के लिए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाया है। अब सरकारी जमीन पर बने स्कूलों को वह शर्त हर हाल में माननी होगी जिसमें कहा गया है कि वे आसपास रहने वाले बच्चों को एडमीशन से मना नहीं करेंगे।

दिल्ली में करीब 400 स्कूल ऐसे हैं, जहां पर नर्सरी ऐडमिशन के लिए सबसे ज्यादा मारामारी देखने को मिलती है। इनमें से 285 ऐसे स्कूल हैं, जो डीडीए की जमीन पर बने हुए हैं। दिल्ली सरकार ने डीडीए अलॉटमेंट लेटर्स की शर्तों के सहारे ही इस बार ऐडमिशन की राह आसान बनाने की तैयारी की है। दरअसल जमीन आवंटन की शर्तों में है कि स्कूल आसपास रहने वाले बच्चों को ऐडमिशन से मना नहीं कर सकते। अलॉटमेंट लेटर्स में नेबरहुड कान्सेप्ट को फॉलो करने की बात है। दिल्ली सरकार अब इसी शर्त को सख्ती से लागू कराएगी । ऐसा होने पर स्कूल से 0–1 किमी की दूरी पर रहने वाले हर बच्चे का ऐडमिशन करीब– करीब निश्चित हो जाएगा।

जनता संतुष्ट तो ठेकेदार को पेमेंट

गली–मोहल्ले में होने वाले विकास कार्यों की क्वालिटी से जब तक वहां के लोग संतुष्ट न हों, तब तक ठेकेदार का पेमेंट न किया जाए। इस तरह का प्रयोग दिल्ली के उप–मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी विधानसभा पटपड़गंज में किया है। मनीष सिसोदिया ने पटपड़गंज के वार्ड नंबर 217 और 218 के कुछ मोहल्लों में हुए 15 विकास कार्यों का निरीक्षण किया। लोगों से काम की क्वालिटी के बारे में पूछा। जहाँ लोगों ने संतुष्टि जाहिर की, वहाँ पर ठेकेदार को पेमेंट के निर्देश दिए। एक जगह लोग काम से संतुष्ठ नहीं थे, वहाँ ठेकेदार को पेमेंट रोकने को भी कहा।

उप–मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निरीक्षण दौरे का एक वीडियो अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करके लिखा कि वे विधायक फंड से होने वाले हर एक काम की जानकारी काम शुरू होते ही पर्चे के माध्यम से उस गली में बँटवा देते हैं। पर्चे में काम का पूरा विवरण, ठेकेदार, इंजीनियर आदि का फोन नंबर और लागत आदि सब लिखा रहता है। इसका असर ये हुआ है कि लोगों ने सामने खड़े होकर सड़कें बनवाईं और ठेकेदार को वैसा ही काम करने पर मजबूर किया है जैसा पर्चे में लिखा होता है। ठेकेदार को पेमेंट तभी दिया जाता है जब लोगों की तरफ से उन्हें कार्यसंतुष्टि का लिखित पत्र मिल जाता है।

जलबोर्ड ने निकाले रिकॉर्ड बिल

इतिहास में पहली बार दिल्ली जल बोर्ड ने 19 लाख 50 हजार बिल निकाले। यह कुल बिलों का 92 फीसदी है जो कि एक रिकॉर्ड है। साल भर पहले करीब 14 लाख बिल निकलते थे। इसमें बोर्ड की एम सेवा का बड़ा योगदान है। अब मीटर रीडर की जरूरत नहीं रह गई है। दिल्ली जल संसाधन मंत्री कपिल मिश्र ने जल बोर्ड के कुछ अहम फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड ने कमर्शियल कनेक्शन के इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्ज खत्म कर दिया है। अब कनेक्शन के लिए फिक्स रेट लिए जाएँगे। 50 वर्गमीटर से कम जगह के लिए 45000 और 50 वर्गमीटर से बड़ी जगह के लिए 100000 रुपये लिए जाएँगे। इसके अलावा जलबोर्ड के सामुदायिक भवनों का इस्तेमाल आम नागरिक भी कर सकेंगे।

अवैध टैक्सियों पर कार्रवाई

दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने अवैध रूप से चलने वाली ऐप बेस्ड टैक्सियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की है। इस साल जनवरी से अक्टूबर तक 8,291 टैक्सियों के चालान किए गए और 1,873 टैक्सियां जब्त की गई। इनमें ओला–उबर की कैब भी शामिल हैं। सितंबर–अक्टूबर में इस मुहिम में तेजी लाते हुए एनफोर्समेंट विंग ने दिल्ली में कई जगह टीमें लगाई और ज्यादा गाड़ियां जब्त की ऑटो–टैक्सी यूनियनों की मांग रही है कि ऐप बेस्ड टैक्सियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यूनियन का कहना है कि यूपी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में रजिस्टर्ड गाड़ियां दिल्ली के लोकल रूट्स पर चल रही हैं। इससे दिल्ली में रजिस्टर्ड ऑटो–टैक्सियों का बिजनेस बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इसी के साथ अवैध रूप से चलने वाले ई–रिक्शा के भी काफी चालान किए गए। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के भी काफी रिक्शा चल रहे थे। कुछ के पास लाइसेंस तक नहीं था।

शुरू हुआ मुकुंदपुर फ्लाईओवर

मुकुंदपुर चौक पर 6 लेन फ्लाईओवर शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसका उद्घाटन किया। इस फ्लाईओवर के बनने के बाद विकासपुरी से वजीराबाद का करीब 22.5 किमी का सफर आसान हो गया। मुकुंदपुर चौक पर 6 लेन फ्लाईओवर निर्माण के लिए 62 करोड़ का बजट तय किया गया था, लेकिन यह करीब 50 करोड़ रुपये में बनकर तैयार हो गया है। 900 मीटर लंबे इस फ्लाईओवर को बनाने में करीब तीन साल का समय लगा। नवंबर 2013 में यह प्रॉजेक्ट शुरू किया गया था और नवंबर 2016 में यह फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया है। 3–3 लेन के रोड बनाए गए हैं। साथ ही साइकल ट्रैक और फुटपाथ भी बनाया गया है। एनएच–1 से गुजरने वालों को इस फ्लाईओवर से काफी फायदा होगा। प्रदूषण में भी कमी होगी और लोगों का समय भी बचेगा। इस फ्लाओवर से हर रोज डेढ़ लाख से ज्यादा वाहनों के गुजरने की उम्मीद है। ट्रैफिक जाम से भी छुटकारा मिलेगा और लोगों का बहुत समय बचेगा। फ्लाईओवर के दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट भी बनाई गई है। ■

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ 'ਹਰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ' ਅਭਿਆਨ

ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ, ਪਾਠ ਨਾਲ ਪਿਆਰ !

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 3.5 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ 'ਪੜ੍ਹਨ' ਦਾ ਮਤਲਬ

''ਮੇਰੇ ਗਰੁਪ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਖਰ ਪਹਿਚਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ''ਵਹਾਟਸ ਏਪ ਗਰੁਪ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿੱਕਤ ਦੱਸੀ।

''ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਕ ਬੱਚਾ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜੋ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ?'' ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਐਸਐਮਸੀ (ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ।

''ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ'' - ਕਲਾਸ ਸੱਤ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ।

''ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਵਾ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ''ਕਲਾਸ ਛੇ ਦੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।

''ਮੈਂ ਗਣਿਤ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਲਾਸ ਅੱਠ ਦੇ ਦਸ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਦਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੇਮਾਨ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਪਾਉਣਗੇ।''

Yogesh Kumar

रीडिंग मेले में खेल खेल में सीखा पढ़ना

प्रस, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार के एजुकेशनल कैंपेन 'रीडिंग मेले' में रविवार को स्टूडेंट्स अपने पैरंट्स के साथ पहुंचे। सरकार इन मेलों के साथ क्लास 6 से 8 तक के हर बच्चे को अपनी किताबें पढ़ने लायक बनाने की चुनौती को पूरा करने की कोशिश में है। हर बच्चे को पढ़ना सिखाने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर ने टीचर्स डे के दिन बाल दिवस यानी आज की डेडलाइन रखी थी। कैंपेन के तहत हर संडे रीडिंग मेले लगाए गए, करीब 250 मेलों में बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स और उनके पैरंट्स भी पहुंचे।

स्कूल मैनेजमेंट कमिटी ने इस मेलों को ऑर्गनाइज किया और कई ऐसे टूल और एक्टिविटी का इस्तेमाल किया ताकि बच्चे मजेदार तरीके से पढ़ना सीख सकें। मेलों में तमाम एक्टिविटी और गेम रखे गए ताकि बच्चा अक्षर, शब्द, वाक्य और पैराग्राफ पढ़ना सीख सकें। रविवार को नंद नगरी इलाके में लगे रीडिंग मेले में भी बच्चों ने खेल खेल में पढ़ना सीखा।

ਬਦਲੀ ਜਮਾਤ 6, 7 ਅਤੇ 8 ਦੀ ਸੂਰਤ !

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਤ ਛੇ, ਸੱਤ ਅਤੇ ਅੱਠ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 6,32370। 'ਹਰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ 57 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 3,59,152 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਲਿੱਖਿਆ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਘੱਟ ਸੀ। 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਹੇ।

ਕਲਾਸ – 6 –

- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਲਾਸ ਛੇ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 46 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।
- 32 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਸਨ ਜੋ ਕਲਾਸ ਇਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ।
- ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ।

ਕਲਾਸ – 7 –

- ਕਲਾਸ ਸੱਤ ਦੇ 52 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਸਨ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਇਹ ਆਂਕੜਾ 64 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।
- 24 ਫੀਸਦੀ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਕਲਾਸ 1 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਂਕੜਾ ਘੱਟ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
- ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਾ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ।

ਕਲਾਸ – 8 –

- ਕਲਾਸ ਅੱਠ ਦੇ 55 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਲ 68 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ।
- ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਸਨ ਜੋ ਕਲਾਸ ਇਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਂਕੜਾ ਘੱਟ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
- ਕਲਾਸ ਅੱਠ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ 4 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਆਂਕੜਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਯਾਨੀ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਯਾਨੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਲਾਸ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਵਿਆਪਕ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡਾ. ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਪੰ. ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੋਖਾ ਰੰਗ ਭਰ ਦਿਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੋਖਾ "14 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ" ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਤੇ ਉਪਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਯਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਹੁੰ ਲਈ ਕਿ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਤਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਟਿਪਣੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਿਤਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ

ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਪਾਏ। ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਾਸ ਛੇ ਦੇ 74 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 31 ਫੀਸਦੀ ਐਸੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਜੋ ਕਲਾਸ ਇਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਨੋ ਡਿਟੇਂਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਲਾਸ 7 ਅਤੇ 8 ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਐਸੇ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਇਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ।

ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤਕ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਐਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਠੀਕ ਨਾਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1016 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਲਾਸ ਛੇ, ਸੱਤ ਅਤੇ ਅਠ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ 6.3 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਕਾਬਲ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 185 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸੋਰਸ ਗਰੁਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਂਟਰ ਟੀਚਰ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਮੇਂਦਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਮੇਲਾ ਬਤੌਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਸਐਮਸੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਅਨੁਭਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ 522 ਰੀਡਿੰਗ ਮੇਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਤੇ 71000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੇਗਾ ਪੀਟੀਐਮ (ਪੇਰੇਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ।■

'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਈਲ' ਨਾਲ ਚਮਕਣਗੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ।

'ਹਰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਈਲ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਅੱਖਰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਐਸੇ 35,000 ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ' ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਇਕ ਬਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਰੀਡਿੰਗ ਮੇਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਅੱਖਰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਪਾਏ। ਐਸੇ ਹੀ 35,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਈਲ'' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਟਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਮੇਂਦਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਯਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ 'ਹਰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ' ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਈਲ' ਦੇ ਜਰੀਏ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਛੁੱਟ ਨਾ ਪਾਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਗਰੁਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੀਚਰਸ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਖਾਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਖਿਆ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਯ ਵਿਚ ਇਕ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖੇਗੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਐਮਆਰਆਈ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ !

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ ਹੁਣ ਐਮਆਰਆਈ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਫਤ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਸ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗਲਬਾਤ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

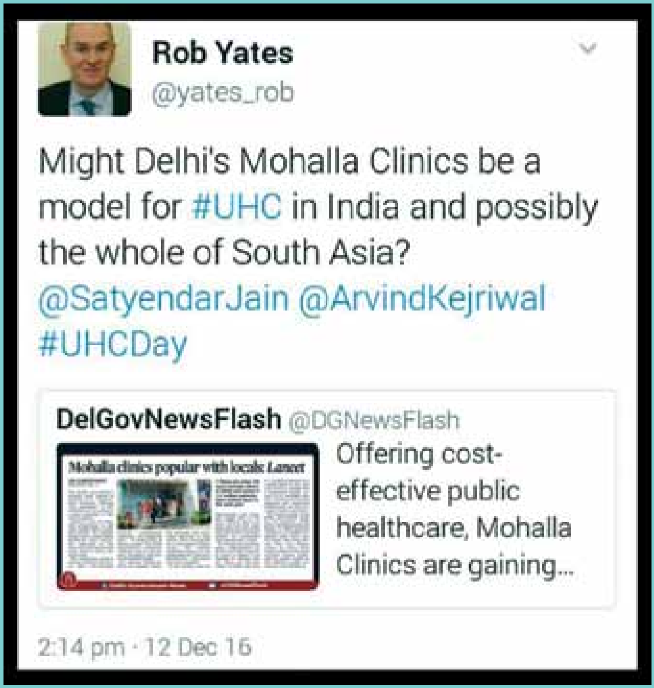

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਮਆਰਆਈ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਮਨਿਸਟਰ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਐਮਆਰਆਈ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਐਮਆਰਆਈ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਦੀ ਗਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਆਰਆਈ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਅਤੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮਆਰਆਈ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਜੇ 7 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਰੋਗਯ ਕੋਸ਼ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ 11ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸੌ ਡੇਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 100 ਆਮ ਆਦਮੀ ਡੇਂਟਲ ਕਲੀਨਿੰਕ ਖੋਹਲੇਗੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਪਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਯਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਡੇਂਟਲ ਸਾਈਂਸੇਸ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਡੇਂਟਲ ਹੇਲਥ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਂਟਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੰਜ ਸੇਂਟਰ ਹੋਰ ਖੋਹਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਡੇਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਹਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡੇਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ।

'ਦ ਲਾਨਸੇਂਟ' ਨੇ ਸਲਾਹਿਆ 'ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ'

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਤੇ ਲਾਨਸੇਂਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇਸ ਬੇਹਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਰਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿਛੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਨਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।

ਉਧਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਇਕ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਸ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

World Report

Delhi looks to expand community clinic initiative

Sections

The Washington Post

Innovations

What New Delhi's free clinics can teach America about fixing its broken health care system

ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਮਆਰਆਈ-ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਫ੍ਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਘਟ-ਤੋਂ-ਘਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਕਮ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਬ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਕਾਰਡ, ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੋ ਮਰੀਜ ਭਰਤੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਵਿਚ ਐਮਆਰਆਈ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ। ਓਪੀਡੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮਰੀਜ ਇਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਇਨਕਮ 3 ਲਖ ਰੁਪੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪਰਚਾ, ਇਨਕਮ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ■

ਐਮਸੀਡੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਾਨ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਣਗੇ ਐਮਸੀਡੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ

ਐਮਸੀਡੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਂ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਐਮਸੀਡੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਟੀਚਰਸ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਸਲਿਪ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਸਲਿਪ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਤੋਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਐਮਸੀਡੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਤਕ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਫੀਡਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਲਿੰਕ ਸਕੂਲਾਂ' ਵਿਚ 6ਵੀਂ ਵਿਚ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਕਟਣ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਸੀਡੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੇਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਯਾ ਨੇ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ 'ਚੁਣੌਤੀ' ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ■

ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ

ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਚਰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀਟੇਟ) ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਛਤਰਸਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿਕਤਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਕਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 8000 ਨਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਮਾਰਚ ਤਕ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 8000 ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੈਨਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੈਅ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਟੇਟ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 44 ਫੀਸਦੀ ਦਾ

ਤੈਅ ਤਨਖਾਹ, 8 ਛੁੱਟੀਆਂ !

ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ 700 ਰੁਪੈ ਰੋਜਾਨਾ ਅਤੇ 17500 ਰੁਪੈ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪੈ ਰੋਜਾਨਾ ਜਾਂ 25000 ਰੁਪੈ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 800 ਰੁਪੈ ਰੋਜਾਨਾ ਅਤੇ 20000 ਰੁਪੈ ਮਹੀਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਜੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 26,250 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤ ਮਹੀਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਦਿਤੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ 17000 ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 15000 ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਟੇਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੈਅ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਸੀਟੇਟ) ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ 700 ਰੁਪੈ ਰੋਜਾਨਾ ਅਤੇ 17500 ਰੁਪੈ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 33200 ਰੁਪੈ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਧਰ ਟੀਜੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 33,120 ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 800 ਰੁਪੈ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪੈ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਜੀਟੀ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 34,100 ਰੁਪੈ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 22500 ਰੁਪੈ ਜਾਂ 900 ਰੁਪੈ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸਨ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਧਰ ਤੇ ਹੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਟੀਜੀਟੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀਟੀ ਨੂੰ http://www.edudel.nic 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਖਾਸਤ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਸਮਿਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਇਕ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਐਸਐਮਸੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾਵਾਰ ਪੈਨਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਇਕ ਅਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਅਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਯਕੀਨੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਜਿੰਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ■

ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ – ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ

ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੇਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਖੋਹਲਣਾ, ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵੰਡਣਾ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਬਨਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਨੇ-ਬਾਨੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੋ । ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਉ। ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਘੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਹਿਰ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਜਰੀਏ ਘੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ

ਮਾਈਂਡਸੇਟ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਏ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਂਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇਐਨਯੂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪਧਰੀ ਰਿਸਰਚ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਰਹੇ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਦਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਮੂਹ, ਸੰਪਰਦਾਏ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ-ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਨੇ-ਬਾਨੇ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਨ, ਮਦਰਸੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਵਰਡ ਲੁਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ, 50 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।

(ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਐਂਟੀ-ਪੀਪਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ' ਦੁਆਰਾ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਟੇਸਟ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ)

ਨਿਰਭੈਯਾ ਸਦਾ: ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਵਿਚ 'ਏ ਵੂਮਨ ਅਲੋਨ' ਦਾ ਮੰਚਨ

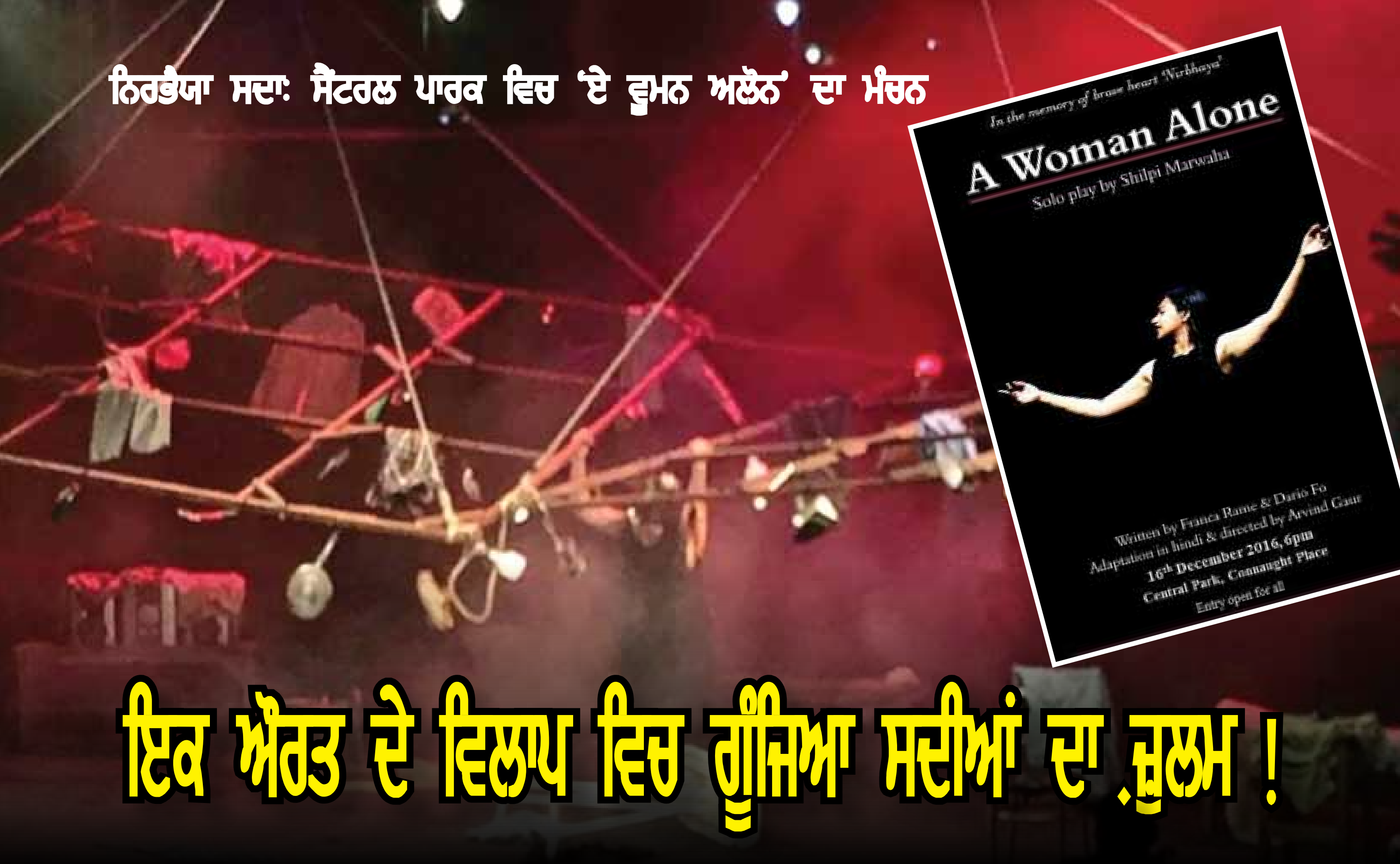

ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਲਾਪ ਵਿਚ ਗੂੰਜਿਆ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ !

ਸੱਤਰ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਾਰਿਯੋ ਫੋ ਅਤੇ ਫ੍ਰਾਂਕਾ ਰਾਮੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ-ਏ ਵੂਮਨ ਅਲੋਨ ਯਾਨੀ ਇਕ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇਪਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁੱਖ-ਦੁੱਖ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨਿਰਭੈਯਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾਟਕ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੋਮੂੰਹੇਪਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਦਰਜ਼ਾ ਹੇਠਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸਦੀਓਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਿਰਭੈਯਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ 'ਨਿਰਭੈਯਾ ਸਦਾ' ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੋਹਰਾਏ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਝਾਂਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਅਸਿਮਤਾ ਥਿਏਟਰ ਗਰੁਪ ਦੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਗੌੜ ਨੇ ਅਤੇ ਅਭਿਨੈ ਸੀ ਸ਼ਿਲਪੀ ਮਾਰਵਾਹ ਦਾ। ਚੁਸਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਅਭਿਨੈ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਔਰਤ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਉਧੇੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਸਿਹਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੈਂਗਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਦਸੂਰਤ ਚੇਹਰਾ ਉਭਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦਾ ਅੰਤ ਇਕ ਵਿਲਾਪ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਨਾਟਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਯਾ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਝਿੰਜੋੜ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੈਂਗਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮ ਬਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੀਕਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸਰਾਪਗ੍ਰਸਤ ਹੋਵੇ ਅਸੁੰਦਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਸਾ ਦੋਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸੁੰਦਰ ਬਣਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਨਿਰਭੈਯਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ■

ਤੈਅ ਤਨਖਾਹ, 8 ਛੁੱਟੀਆਂ !

1 ਕਿਮੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਡਮੀਸ਼ਨ

ਨਰਸਰੀ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਅਫਰਾਤਫਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਬਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਮੰਨਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 400 ਸਕੂਲ ਐਸੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਨਰਸਰੀ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 285 ਐਸੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜੋ ਡੀਡੀਏ ਦੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਡੀਏ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਹ ਅਸਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਮੀਨ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰਸ ਵਿਚ ਨੇਬਰਹੁਡ ਕਨਸੇਪਟ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਏਗੀ। ਐਸਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 0-1 ਕਿਮੀ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਜਨਤਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਪੇਮੇਂਟ

ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਵਾਲਿਟੀ ਤੋਂ ਜਦ ਤਕ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਦ ਤਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਪੇਮੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਯਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਪਟਪੜਗੰਜ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਯਾ ਨੇ ਪਟਪੜਗੰਜ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 217 ਅਤੇ 218 ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ 15 ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਕਵਾਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ। ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੇਮੇਂਟ ਦੇ ਆਡਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਪੇਮੇਂਟ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਉਪ-ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਯਾ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰੇ ਦਾ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁਕ ਪੇਜ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਫੰਡ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਕ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਸ ਗਲੀ ਵਿਚ ਵੰਡਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਦਿ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਆਦਿ ਸਭ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੈਸਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਾ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੇਮੇਂਟ ਤਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਲਿਖਿਤ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਦਾ ਹੈ।

ਜਲਬੋਰਡ ਨੇ ਕੱਢੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਲ

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ 19 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਲ ਕੱਢੇ। ਇਹ ਕੁਲ ਬਿਲਾਂ ਦਾ 92 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਬਿਲਾਂ ਦਾ 92 ਫੀਸਦੀ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸਾਲ ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਬਿਲ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਐਮ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। 50 ਵਰਗਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ 45000 ਅਤੇ 50 ਵਰਗਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ 100000 ਰੁਪੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਨਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪ ਬੇਸਡ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ 8,291 ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,873 ਟੈਕਸੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਓਲਾ-ਓਬਰ ਦੀਆਂ ਕੈਬਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਆਟੋ-ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਬੇਸਡ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ, ਰਾਜਿਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਲ ਰੂਟਸ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਟੋ-ਟੈਕਸੀਆਂ ਦਾ ਬਿਜਨੇਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਿਨਾ ਫਿਟਨੇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੁਕੁੰਦਪੁਰ ਫਲਾਈਓਵਰ

ਮੁਕੁੰਦਪੁਰ ਚੌਕ ਤੇ 6 ਲੇਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਯਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਤੋਂ ਵਜੀਰਾਬਾਦ ਦਾ ਕਰੀਬ 22.5 ਕਿਮੀ ਦਾ ਸਫਰ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਕੁੰਦਪੁਰ ਚੌਕ ਤੇ 6 ਲੇਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ 62 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 900 ਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ। ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 3-3 ਲੇਨ ਦੇ ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਫੁਟਪਾਥ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਐਚ-1 ਤੋਂ ਗੁਜਰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ। ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੇਲਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

مختصر میں...

1 کلو میٹر دائرے کے ہر بچے کا ایڈمیشن

نرسری داخلہ کولیکر ہر سال ہونے والی افراتفری کوختم کرنے کے لئے دہلی سرکار نے سخت قدم اٹھائے ہیں۔اب سرکاری زمین پر بنے اسکولوں کو ہر شرط ہرحال میں ماننی ہوگی جس میں کہا گیا ہے کہ وہ آس پاس رہنے والے بچوں کوایڈمیشن سے منع نہیں کریں گے۔

دہلی میں قریب 400 اسکول ایسے ہیں جہاں پر نرسری ایڈمیشن کے لئے سب سے زیادہ مارا ماری دیکھنے کوملتی ہے۔ان میں سے 285 ایسے اسکول ہیں جوڈی ڈی اے کی زمین پر بنے ہوئے ہیں۔دہلی سرکار نے ڈی ڈی اے الاٹمنٹ لیٹرس کی شرط کے سہارے ہی اس بار ایڈمیشن کی راہ آسان بنانے کی تیاری کی ہے ۔ دراصل زمین الاٹمنٹ کی شرطوں میں ہے کہ اسکول آس پاس رہنے والے بچوں کوایڈمیشن سے منع نہیں کرسکتے۔الاٹمنٹ لیٹرس میں نیبر ہوڈ کانسیپٹ کو فالو کرنے کی بات ہے۔دہلی سرکار اب اسی شرط کوسختی سے لاگوکرائے گی۔ایسا ہونے پر اسکول سے 1-0 کلومیٹر کی دوری پر رہنے والے ہر بچے کوایڈمیشن قریب- قریب طے ہوجائے گی۔

عوام مطمئن تو ٹھیکیدار کو پیمنٹ

گلی- محلّہ میں ہونے والی ترقی کاموں کی کوالٹی سے جب تک وہاں کے لوگ مطمئن نہیں ہوں،تب تک ٹھیکیدار کوپیمنٹ نہ کیا جائے۔اس طرح کا استعمال دہلی کے نائب وزیراعلیٰ منیش سسودیا نے اپنے اسمبلی حلقہ پٹپڑ گنج میں کیا ہے۔منیش سسودیا نے پٹپڑ گنج کے وارڈ نمبر 217 اور 218 کے کچھ محلّہ میں ہوئے 15 وکاس کے کاموں کا معائنہ کیا۔لوگوں سے کام کی کوالٹی کے بارے میں پوچھا۔ جہاں لوگوں نے اطمینان ظاہر کی،وہاں پر ٹھیکیدار کوپیمنٹ کی ہدایت دیئے۔ایک جگہ لوگ کام سے مطمئن نہیں تھے، وہاں ٹھیکدار کوپیمنٹ روکنے کوبھی کہا۔ نائب وزیراعلیٰ منیش سسودیا نے معائنہ دورے کا ایک ویڈیو اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کرکے لکھا کہ وہ ایم ایل اے فنڈ سے ہونیوالے ہرایک کام کی جانکاری کام شروع ہوتے ہی پرچے کے ذریعہ اس گلی میں تقسیم کروادیتے ہیں۔ پرچے میں کام کا پوری تفصیل ٹھیکدار،انجینئر وفون نمبر تخمینہ سب لکھا رہتا ہے۔اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے سامنے کھڑے ہوکر سڑکیں بنوائی اور ٹھیکیدار کوویسا ہی کام کرنے پر مجبور کیا ہے جیسا پرچے میں لکھا ہوتا ہے۔ٹھیکیدار کوپیمنٹ تبھی دیا جاتا ہے جب لوگوں کی طرف سے انہیں کام مطمئن کا تحریری لیٹرل جاتا ہے۔

جل بورڈ نے نکالے ریکارڈ بل

تاریخ میں پہلی بار دہلی جل بورڈ نے 19 لاکھ 50 ہزار بل نکالے۔ یہ کل بلوں کا 92 فیصدی ہے جوکی ایک ریکارڈ ہے۔سال بھر پہلے قریب 14 لاکھ بل نکالے تھے۔اس میں بورڈ کی اہم خدمات کا بڑا تعاون ہے۔اب میٹر ریڈر کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔دہلی جل بورڈ وزیر کپل مشرا نے جل بورڈ کے کچھ اہم فیصلوں کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ بورڈ نے کمرشل کنیکشن کے انفرااسٹرکچر چارج ختم کردیا ہے اب کنیکشن کیلئے فکس ریٹ لئے جائیں گے۔50 گز سے کم جگہ کیلئے 45000 ہزار اور 50 گز سے بڑی جگہ کیلئے 100000 روپے لئے جائیں گے۔اس کے علاوہ جل بورڈ کے سامود ایک بھونوں کا استعمال عام لوگ بھی کرسکیں گے۔

غیر قانونی ٹیکسیوں پر کارروائی

دہلی سرکار کے ٹرانسپورٹ محکمہ نے غیرقانونی ڈھنگ سے چلنے والی ایپ بیسڈ ٹیکسیوں کیخلاف کارروائی تیز کی ہے۔ اس سال جنوری سے اکتوبر تک 8.291 ٹیکسیوں کے چالان کئے گئے اور 1.873 ٹیکسیاں ضبط کی گئی۔ ان میں اولا-اوبیر کی کیب بھی شامل ہیں۔ستمبر اکتوبر میں اس مہم میں تیزی لاتے ہوئے انفارسمنٹ ونگ نے دہلی میں کئی جگہ ٹیمیں لگائی اور زیادہ گاڑیاں ضبط کی آٹو - ٹیکسی یونینوں کی مانگ رہی ہے کہ ایپ بیسڈ ٹیکسیوں کیخلاف بڑی کارروائی کی جائے۔یونین کا کہنا ہے کہ یوپی،راجستھان، پنجاب اور ہریانہ میں رجسٹرڈ گاڑیاں دہلی کے لوکل روڈس پر چل رہی ہیں۔اس سے دہلی میں رجسٹرڈ آٹو- ٹیکسیوں کا بزنس بُری طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے۔اسی کے ساتھ غیر قانونی ڈھنگ سے چلنے والے ای-رکشا کے بھی کافی چالان کئے گئے۔بنا فٹنیس سرٹی فکیٹ کے بھی کافی رکشا چل رہے تھے۔کچھ کے پاس لائسنس تک نہیں تھا۔

شروع ہوا مکند پور فلائی اوور

مکند پور چوک پر 6 لین فلائی اوورشروع ہوگیا ہے۔ نائب وزیراعلیٰ منیش سسودیا نے اس کا افتتاح کیا۔اس فلائی اوور کے بننے کے بعد وکاسپوری سے وزیرآباد کا قریب 22.5 کلومیٹر کا سفر آسان ہوگیا۔مکند پور چوک پر 6 لین فلائی اوورتعمیر کیلئے 62 کروڑ کا بجٹ طے کیا گیا تھا،لیکن یہ قریب 50 کروڑ روپے میں بن کر تیار ہوگیا ہے۔ 900 میٹر لمبا یاس فلائی اوورکو بنانے میں قریب تین سال کا وقت لگا۔نومبر 2013 میں یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا اور نومبر 2016 میں یہ فلائی اوور بن کر تیار ہوگیا ہے۔ 3-3 لین کے روڈ بنائے گئے ہیں۔ساتھ ہی سائیکل ٹریک اور فٹ پاتھ بھی بنایا گیا ہے۔این ایچ 1- سے گزرنیوالوں کواس فلائی اوور سے کافی فائدہ ہوگا۔آلودگی میں بھی کمی ہوگی اورلوگوں کا وقت بھی بچے گا۔اس فلائی اوور سے ہرروز ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ گاڑیوں کے گزرنے کی امید ہے۔ٹریفک جام سے بھی چھٹکارا ملے گا اورلوگوں کا بہت وقت بچے گا۔فلائی اوور کے دونوں طرف گرین بیلٹ بھی بنائی گئی ہے۔

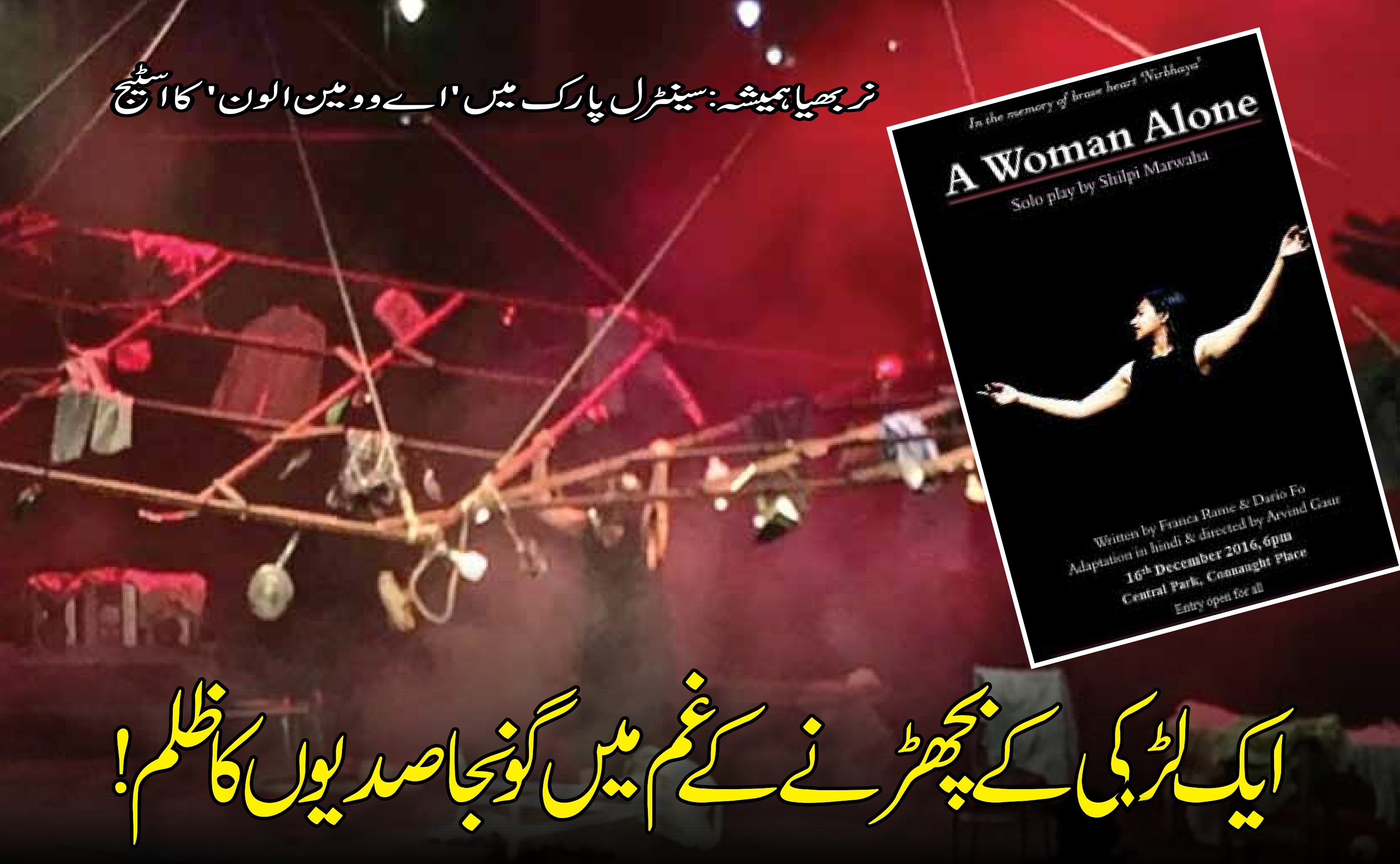

نربھیا ہمیشہ: سینٹرل پارک میں 'اے وومین الون' کا اسٹیج

ایک لڑکی کے بچھڑنے کے غم میں گونجا صدیوں کا ظلم!

ستّر کے زمانہ میں نوبل انعام یافتہ سے نوازے گئے اٹلی کے بڑے ناٹک کار داریو فو اور فرانکا رامے نے مل کر ایک ناٹک لکھا تھا - اے وومین آلون یعنی ایک اکیلی عورت۔ اس ناٹک میں ایک عورت ہے جس کا شوہر اسے گھر میں بند کر کے چلا گیا ہے اور وہ تنہائی میں اپنی زندگی کی سکھ۔دکھ بیان کرتی ہے۔16 ستمبر کی شام نربھیا کی یاد میں یہ ناٹک کناٹ پلیس کے سینٹرل پارک میں کھیلا گیا اور سماج کے دومنہے پن اور عورت کو انسان سے ایک درجہ نیچے سمجھنے کی اس کی صدیوں پرانی سمجھ کو بے پردہ کر گیا۔

یوں تو نربھیا سانحہ کی برسی پر دہلی میں تمام پروگرام ہوئے لیکن دہلی حکومت کا 'نربھیا سدا' اس مطلب میں خاص تھا کہ اس میں عورتوں کے متاثرہ کے نام پر پرانے نعرے نہیں دہرائے گئے بلکہ عورتوں کے من میں جھانکنے کی کوشش کی گئی اور عورت کے نظریئے سے عزت کو دیکھا گیا۔ سنٹرل پارک میں اسمتا تھیٹر گروپ کی طرف سے پیش کئے گئے اس ناٹک کا ہدایت کار تھا اروند گوڑ، اور کلا کار تھا شلپی مارواہ کا ۔چست ہدایت کار اور درست کردار کا ہی اثر تھا کہ رشتوں کے تناؤ میں الجھی عورت من کی پرتیں ادھیڑنے کے ساتھ شائقین سہر رہے تھے۔ ہر رشتے کی آڑ میں عورت کے شکار ہونے کی یہ قصہ وہ آئینہ ہے جس میں ہم جنس برابر ہی نہیں عورت کے استحصال کو روایت بنا دینے والوں کا بدصورت چہرہ ابھرتا ہے۔ناٹک کا آخر ایک رنج وغم سے ہوا جس نے سماج کو بدلنے اور عورتوں کے تئیں کشیدگی ہونے کی چنوتی پیش کی جس کے بنا انسانیت کا سفر پورا نہیں ہوتا۔

ناٹک کے بعد دہلی کے نائب وزیر اعلی جناب منیش سسودیا کے مختصر خطاب نے شائقین کے غور وفکر کو جھنجھوڑ دیا۔انہوں نے کہا کہ ہماری تعلیم نظام کی ہم جنس برابری کی بنیاد ڈالتی ہے،جس میں سیتا ہمیشہ رسوئی میں کام کرتی ہے اور رام بازار جاتا ہے ۔افسانوں قصوں میں بھی ایک خوبصورت راجکماری کو بددعا دی گئی ہو بدصورت ہونے اور پھر پری کے آشیرواد سے خوبصورت ہونے کا قصہ دہرایا جاتا ہے اور سماج بازار کے شرائط وضوابط کیمطابق خوبصورت بننے کی ہوڑ میں پھنس جاتا ہے۔ دہلی کے ثقافتی وزیر کپل مشرا نے کہا کہ ملک میں قانون بہت ہیں ، لیکن ہمیں لوگوں کو بیدار کرنا ہے ۔پروگرام میں نربھیا کے والدین بھی موجود تھے۔

مستقل طور سے یہ زہر گھولنا۔ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ اگر تعلیم میں یہ لوگ مذہب اور فرقہ کا زہر گھولنے میں کامیاب ہوگئے تو اسکول اور کالجوں کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا۔ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ جنہیں ہم اسکول کالج کہتے ہیں۔کل انھیں اسپتالوں کی برانچ نہ کہا جانے لگے۔

وزیر تعلیم ہونے کی ناطے میری یہ ذمہ داری ہے کہ ملک کی یونیورسٹیز، اسکولوں، کالجوں کو مذہب ونسل کی سیاست کا اکھاڑہ ہونے سے بچایا جائے۔ملک کی سب سے معزز یونیورسٹی جے این یو کو بدنام کر کے رکھ دیا گیا ہے۔آئی آئی ٹی اور منیجمنٹ اور انسٹی ٹیوٹس سے عالمی سطح کی ریسرچ کی خبریں نہیں آ رہی، بلکہ سرکار اور تنظیموں کے بیچ سیاسی ٹکراؤ کی خبریں آ رہی ہیں جو وائس چانسلر سرکار کی پالیسوں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیک رہے، جو ان کی من چاہی زہر بھری پالیسیوں کو لاگو کرنے سے منع کرتے ہیں، انھیں پریشان کیا جا رہا ہے۔

دہلی کے وزیر تعلیم ہونے کے ناطے ان کی مخالفت کرنا میری ذمہ داری ہے۔میری مخالفت کسی ایک فرقہ یا مذہب سے نہیں ہے۔میرا مقصد ہے کہ ملک کے اسکولوں اور کالجوں کے کسی ذاتی یا مذہب کی سیاست کا اکھاڑا بننے سے بچانا۔اسکولوں اور کالجوں میں ہمیں اچھے انسان اور اچھے پروفیشنلس تیار کرنے ہیں، مذہب اور فرقہ میں الجھی بھیڑ نہیں۔بھارت کے تانے بانے میں مشنری اسکول بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں اور سرسوتی شیشو مندر بھی ہیں۔لیکن بھارت کے اسکولوں میں پڑھائی جانے والے نصاب تعلیم کے پیچھے کی سوچ سائنسی ہونی چاہئے۔فارورڈ لوکنگ ہونی چاہئے۔ہم نے پچاس سال پرانے نہیں، پچاس سال آگے کے بھارت کے لوگ تیار کرنے ہیں۔

اسلئے یہ آواز اٹھنی ضروری ہے کہ ہم ملکر کسی بھی ایسی کوشش کی مخالفت کریں جو اسکولوں، کالجوں کو کسی ایک مذہب یا فرقہ کی تعلیم کا مرکز بنا دے۔اور میں بھروسہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایسے کسی بھی لڑائی میں میں آپ کے ساتھ ہوں۔

(مرکزی سرکار کی مجوزہ تعلیم نیتی کے مخالفت میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی اگینٹس دی اینٹی پیپل ایجوکیشن پالیسی کے ذریعہ
17 نومبر کو سنسد مارگ پر منعقد پروٹسٹ میں دی گئی تجویز)

تعلیم کو فرقہ واریت کے زہر سے بچانا ہوگا۔منیش سسودیا

میں دہلی کا وزیر تعلیم ہوتے ہوئے بھی تعلیم پر ہو رہے اس پروٹیسٹ میں شامل ہوں تو اس لئے کیونکہ مجھے بھی تعلیم کی فکر ہے۔مجھے اس بات کی فکر ہے کہ تعلیم کا مطلب صرف اسکول کھولنا، مڈ ڈے میل بانٹنا یا کمرے بنوانا نہیں ہے۔تعلیم کا مطلب صرف ٹیچر کا اپوائنٹ منٹ کرنا نہیں ہے۔جس وقت مرکز کی اختیار میں بیٹھے لوگ، پورے ملک میں سماجک تانے بانے کو توڑ رہے ہیں، جس طرح سے اپنی حکمتوں سے کاروبار کی کمر توڑ رہے ہیں۔جس طرح مذہب اور نسلوں کے نام پر لڑائی کروا کر سماج کو بانٹا جا رہا ہے۔

اس سازش کے بیچ تعلیم کی تمہید اہم ہو جاتی ہے۔لیکن آج میں اس فکر میں شامل ہونے آیا ہوں کہ تعلیم کو بھی اسی طرح زہریلا بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔

شازش رچی جا رہی ہے کہ کسی طرح تعلیم کو بدل دو۔اسے برباد کر دو۔جو زہر سیاست کے ذریعہ گھولنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، وہی زہر ایجوکیشن میں زہر گھولنے کا مطلب ہے کہ ملک کی آنے والی نسل کے مائنڈ سیٹ میں

پرنسپل کو استاذ مقرر کرنے کا حق

دہلی کی کیجریوال سرکار نے سرکاری اسکول کے پرنسپلوں کو اب ضرورت کے حساب سے ریٹائر استاذ کو مقرر کرنے حق دیدیا ہے۔استاذ کی کمی اور موجودہ استاذ کی ٹریننگ یا چھٹیوں پر جانے کی حالت میں بچوں کی پڑھائی کا نقصان نہ ہو،اسلئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔

دہلی سرکار کے مطابق اگر کسی اسکول میں کسی سبجیکٹ کے ٹیچر کی کمی ہے،تو اب پرنسپل کو ڈپٹی ڈائرکٹر کو کہنے اور فائل بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔اب اسکول کے معیار پر ہی پریشانی کا حل ہو جائیگا۔

اس کے لئے سرکار اسکول سے ریٹائر ڈ ٹی جی ٹی اور پی جی ٹی کو http://www.edudel.nic پر جا کر آن لائن درخواست کرنی ہوگی۔درخواست میں وہ اپنی آسانی کے حساب سے اسکول کو چن سکیں گے، پھر متعلقہ اسکول میں ان کا انٹرویو ہوگا۔چننے کی مجلس میں پرنسپل، ایک ٹیچر اور ایس ایم سی کے دو تین ممبر شامل ہونگے۔اس عمل کے تحت چننے کے بعد بھی جو ریٹائرڈ ٹیچر بچ جائیں گے، شعبہ تعلیم ان کا ایک ضلع وار پینل بنائے گا۔مستقبل میں جب بھی کسی اسکول کو استاذ کی ضرورت ہوگی تو وہ اس پینل سے اپنے یہاں ان کا تقرر کر سکے گا۔

اس سے پہلے دہلی سرکار نے ہر اسکول کے پرنسپل کو اپنے یہاں ایک اسٹیٹ منیجر مقرر کرنے کا حق دیا تھا۔اب دہلی کے تقریباً سبھی سرکاری اسکولوں کی ہر شفٹ میں ایک ایک اسٹیٹ منیجر ہیں۔ان کا کام اسکول میں صاف صفائی وغیرہ یقینی کروانا ہے۔پہلے اسکول میں صاف صفائی یقینی کروانے کا پرنسپل یا کسی استاذ کے ذمہ ہوتا تھا اور اس وجہ سے وہ بچوں کی پڑھائی پر پوری توجہ نہیں دے پاتے تھے۔

طے تنخواہ، 8 چھٹیاں!

جن پرائمری اسسٹنٹ ٹیچر کو ابھی 700 سو روپئے ہر روز اور 17 ہزار 500 سو روپئے مہینے میں ملتے تھے، انھیں اب ایک ہزار روپئے ہر روز یا 25000 روپئے مہینے میں دئے جائیں گے۔

اس کے علاوہ 800 سو روپئے ہر روز اور 20000 روپئے مہینے میں پانے والے ٹی جی ٹی ٹیچر کو اب 26250 روپئے ہر مہینے دیئے جائیں گے۔ ■

تنخواہ میں 90 فیصدی سے زیادہ کا اضافہ

وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے عارضی ٹیچروں کے متعلق فیصلے کی جانکاری خود ایک پریس کانفرنس کے ذریعہ دی۔ عارضی ٹیچروں کو خوشخبری دیتے ہوئے انھوں نے کہا کہ سرکار نے سبھی 17000 گیسٹ ٹیچروں کے تنخواہ میں اضافے کی منظوری دیدی ہے۔ ان میں قریب پندرہ ہزار ایسے ہیں جنھوں نے سی ٹیٹ پاس کرلیا ہے۔ ان ٹیچروں کو ہر مہینے طے تنخواہ ملے گی۔ اسسٹنٹ پرائمری ٹیچر (سی ٹیٹ) کو ابھی 700 روپئے روزانہ اور 17500 روپئے ہر مہینے تنخواہ ملتی ہے۔ اب انھیں 33200 روپئے تنخواہ ملے گی۔ وہیں ٹی جی ٹی ٹیچر کو 33120 روپئے مہینے میں تنخواہ ملے گی۔ انھیں 800 روپئے ہر روز کی شرح سے ادائیگی ہوتی تھی۔ مہینے میں انھیں 20000 ہزار روپئے ملتے تھے۔ اسی طرح پی جی ٹی پاس ٹیچرس کو 34100 روپئے مہینہ ملے گی۔ جنھیں پہلے 22500 روپئے یا 900 روپئے روز کے حساب سے ملتے تھے۔

گیسٹ ٹیچروں کو ملے گا

عارضی ٹیچروں کو تحفہ دیتے ہوئے دہلی سرکار نے طے معاوضہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔جن عارضی ٹیچروں نے مرکزی استاد اہلیت امتحان (سی ٹیٹ) پاس کرلیا ہے ان کی تنخواہ میں90 فیصدی سے زیادہ کا اضافہ کیا جائے گا۔ساتھ ہی انہیں اتفاقی چھٹی بھی ملیں گی۔

دہلی کے چھترسال اسٹیڈیم میں عارضی ٹیچروں کو مخاطب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے کہا کہ سرکار نے برابر تنخواہ دینے کا جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا جائے گا۔اس معاملے میں جو بھی تکنیکی دقتیں ہیں انھیں دور کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پچھلے دو سال میں دہلی میں تعلیم میں انقلابی بدلاؤ ہوئے ہیں اور اب پرائیویٹ اسکولوں سے بچے سرکاراسکولوں میں شفٹ ہونے لگے ہیں۔

اس میں عارضی ٹیچروں کا بھی اہم تعاون رہا۔

پی ڈبلیو ڈی وزیر ستیندر جین نے کہا کہ سرکاری اسکولوں میں آٹھ ہزار نئے کلاس روم مارچ تک بن کر تیار ہو جائیں گے۔اس کے علاوہ آٹھ ہزار اور کلاس روم کی بھی تیاری شروع ہوگئی ہے۔غورطلب ہے کہ عارضی ٹیچروں کو ابھی تک کوئی اتفاقی چھٹی نہیں ملتی تھی اسکول نہ آنے پر ان کی تنخواہ کٹتی تھی ساتھ ہی انھیں تنخواہ یومیہ کی بنیاد پر ملتی تھی۔اب انھیں ہر مہینے نئی تنخواہ ملے گی۔

سرکار نے سی ٹیٹ پاس نہ کرسکنے والے دو ہزار عارضی ٹیچروں کی تنخواہ میں بھی قریب 44 فیصدی کا اضافہ کیا ہے۔

ایم سی ڈی اسکولوں کے بچوں کا داخلہ ہوگا آسان

سرکاری اسکول دیں گے ایم سی ڈی ٹیچروں اور بچوں کو پارٹی

ایم سی ڈی اسکولوں سے پانچویں پاس کرنے کے بعد دہلی کے سرکاری اسکولوں میں داخلہ چاہنے والے بچوں کا دہلی سرکار خاص انداز میں استقبال کرے گی۔ان کے ایڈمیشن کی تکنیک تو آسان ہوگی ہی، ایم سی ڈی اسکولوں کی پانچویں کے ٹیچروں کو بلاکر بچوں کے ساتھ ایک پارٹی بھی منعقد کی جائے گی۔

دہلی سرکار کے اس ایڈمیشن پلان کے مطابق اب دہلی کے سرکاری اسکولوں میں چھٹی کلاس میں ایڈمیشن کیلئے بچوں اور سرپرستوں کو اسکول چکر نہیں کاٹنے پڑیں گے۔سرکاری اسکولوں کے پرنسپل اور ٹیچرس 15 مارچ سے 1 اپریل کے درمیان ایم سی ڈی کے اسکولوں میں جائیں گے اور وہاں ان بچوں کو ایڈمیشن سلیپ دیکر آجائیں گے، جن کے ایڈمیشن ان کے اسکولوں میں ہونے ہیں۔سرپرستوں کے پاس یہ ایڈمیشن سلیپ ہوگی اور وہ اسکول میں جاکر اپنے بچے کا ایڈمیشن کروا سکیں گے۔

اس کے علاوہ یہ بھی طے کیا گیا ہے کی 1 سے 15 اپریل کے بیچ کسی ایک دن بچوں اور ایم سی ڈی میں ان کے ٹیچرس کو دہلی سرکار کے اسکول میں خاص طور سے بلایا جائے گا اور ان کیلئے ایک چھوٹی سی پارٹی منعقد کی جائے گی۔ابھی تک ایم سی ڈی کے 'فیڈر اسکولوں' سے پانچویں پاس کرکے دہلی سرکار کے 'لنک اسکول' میں چھٹی میں ایڈمیشن پانے والے بچوں اور ان کے سرپرستوں کو اسکول کے کئی بار چکر کاٹنے پڑتے تھے۔سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ ایم سی ڈی اسکولوں سے ڈاٹا لیکر پورے ایڈمیشن پروسیس کو آن لائن کرلیا جائے گا۔دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے ایم سی ڈی کے ایجوکیشن ڈائریکٹر سے یہ کہا ہے کہ گرمی کی چھٹیوں میں اسکولوں میں سمر کیمپ کا انعقاد کروایا جائے اور 'چنوتی' پلان کے تحت بچوں کی پڑھنے کی قابلیت کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔

’دی لانسینٹ‘ نے سراہا ’محلہ کلینک‘

دنیا کے اعلیٰ میڈیکل جرنل ’دی لانسینٹ‘ نے دہلی سرکار کے محلّہ کلینک منصوبہ کی تعریف کی۔ برطانیہ کے اس بیحد معزز جرنل کا کہنا ہے کہ اس سے عام لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا ہے۔ اس پہل کا مقصد پچھڑی بستیوں تک صحت سے جڑی سہولتیں پہونچانا ہے ملک کے دوسرے صوبے اس ماڈل کو سمجھ رہے ہیں اور اپنانے کو بے تاب ہیں۔

ادھر بڑے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ پہلے ہی محلّہ کلینک کو ایک انوکھا استعمال بتا چکا ہے۔ اخبار نے یہ بھی لکھا تھا کہ امریکی سرکار کو اس سے کچھ سیکھنا چاہیئے۔

ملے گی۔ جو بھی کم سے کم تین سال سے رہ رہے ہونگے، وہ اس اسکیم کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جن کی سالانہ فیملی انکم تین لاکھ ہونی چاہیئے وہ لیب میں جا کر ٹیسٹ کروا سکیں گے اور ان کا پورا خرچ دہلی سرکار اٹھائے گی۔ اگر کسی کے پاس فوڈ سیکوریٹی کارڈ ہے تو اس میں ریزیڈنس اور انکم پروف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سرٹی فکیٹ، آدھار کارڈ، ووٹر آئی کارڈ، لائسنس سے بھی پتہ چلے گا کہ وہ کتنے دنوں سے دہلی میں رہ رہا ہے۔

دہلی سرکار کے اسپتالوں میں دہلی کے جو مریض بھرتی ہیں ان سب کو یہ سہولت ملے گی۔ وزیر صحت جناب ستیندر جین نے بتایا کہ اس سہولت کا فائدہ صرف ان مریضوں کو ملے گا، جو کم سے کم تین سال سے دہلی میں رہ رہے ہیں، ریاستی سرکار کے دس اسپتالوں میں بھرتی دہلی کے باشندگان کے سبھی مریض پرائیویٹ لیب میں ایم آر آئی اور سٹی اسکین کرا سکیں گے۔ او پی ڈی میں آنے والے صرف وہی مریض اس سہولت کا فائدہ اٹھا پائیں گے جن کی سالانہ تنخواہ تین لاکھ روپے یا اس سے کم ہوگی۔ اس کیلئے انھیں ڈاکٹروں کا لکھا پرچا، انکم اور رہائش سرٹی فکٹ دکھانے ہونگے۔

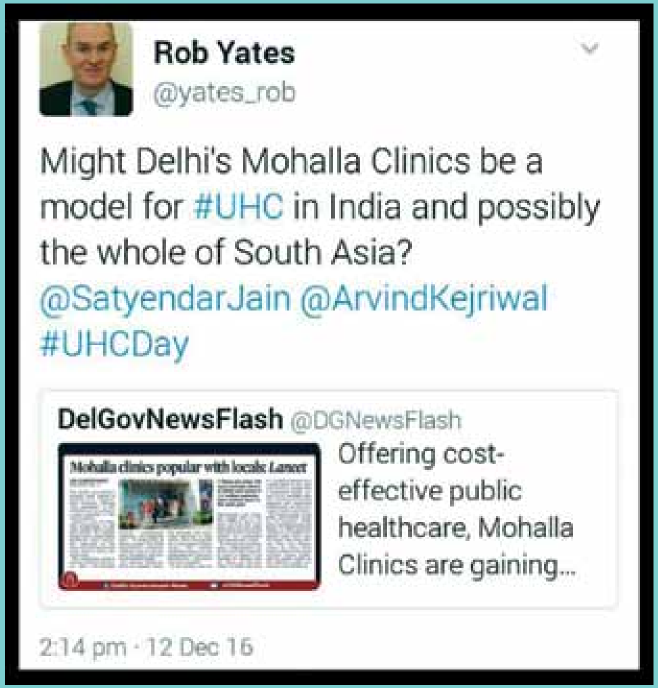

دہلی سرکار نے ضرورت مند مریضوں کیلئے مفت ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین کی سہولت شروع کی۔ وزیر صحت جناب ستیندر جین کے مطابق فلائی اوور بنانے میں ابھی تک 350 کروڑ روپئے سے زیادہ بچائے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے حکم کے مطابق ان پیسوں کا استعمال لوگوں کو بہتر صحت سے جڑی سہولتیں دینے پر کیا جا رہا ہے۔ ستیندر جین نے بتایا کہ دہلی سرکار کے اسپتالوں میں دوائیاں اور بہت سے ٹیسٹ تو پہلے ہی سے فری ہیں، لیکن ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین جیسے بڑے ٹیسٹ بھی اب مفت ہوسکیں گے۔

اسپتالوں میں ایم آر آئی کیلئے تین تین سال کی ویٹنگ کی بات سامنے آنے کے بعد سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ سرکار چاہتی ہے کہ ایم آر آئی کیلئے لوگوں کو انتظار نہ کرنا پڑے اور ایک ہفتہ کے اندر ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین ہوجائے۔ ابھی سات پرائیویٹ لیبس کے ساتھ بات فائنل ہوئی ہے۔ کچھ اور لیبس کے ساتھ بات چل رہی ہے۔

وزیر صحت نے بتایا کہ دہلی اروگیہ کوش گورننگ باڈی کی گیارہویں میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ دہلی کے شہریوں کو فری ایم آر آئی، سی ٹی اسکین کی سہولت

دھلی میں کھلیں گے سو ڈینٹل کلینک

دہلی سرکار دارالحکومت کے الگ الگ علاقوں میں سو عام آدمی ڈینٹیل کلینک کھولے گی۔ محلّہ کلینک کے طور پر ان کلینکوں میں چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا علاج کیا جائے گا۔ اگر دقت زیادہ ہوگی تو مریض کو بڑے اسپتال میں بھیجا جائے گا۔ نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے یہ بات مولانا آزاد انسٹی ٹیوٹ آف ڈینٹل سائنس میں منعقد کئے گئے ڈینٹل صحت میلے کیلئے افتتاحی پروگرام پر کہی۔ اس موقع پر دہلی کے وزیر صحت ستیندر جین نے کہا کہ ڈینٹل کالج کے پانچ سینٹر اور کھولے جائیں گے۔ انھوں نے کہا کہ منھ سے جڑی بیماریوں کا اضافہ ہورہا ہے، لیکن بیداری کی کمی میں لوگ اسپتال تک نہیں پہنچتے، اس لئے چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی جانچ کیلئے ڈینٹل کلینک کھولے جائیں گے۔ ساتھ ہی منھ سے جڑی بیماریوں کیلئے بیداری مہم بھی چلائی جائے گی۔ اس موقع پر انسٹی ٹیوٹ کے پرنسپل اور ڈائرکٹر ڈاکٹر مہیش شرما نے کہا کہ اس طرح ڈینٹل کلینک بنانے میں انسٹی ٹیوٹ پورا تعاون کرے گا۔

دھلی کے نجی اسپتالوں میں مفت ہوگا

ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین!

دھلی سرکار کے دس اسپتالوں میں علاج کرانے والے مریض اب ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین جیسی جانچ پرائیویٹ لیبس میں بھی مفت کرا سکیں گے۔ اس کیلئے سرکار نے سات پرائیویٹ لیبس سے اگریمنٹ کیا ہے۔ کچھ دوسری لیبوں کو اس اسکیم سے جوڑنے پر بات چل رہی ہے۔

لیکن یہ تمسخر ہے کہ تمام بچے اس معیار پر کھرے نہیں اتر پائے۔ جولائی 2016 میں کئے گئے ایک سروے کا نتیجہ تھا کہ درجہ چھ کے 74 فیصدی بچے اپنی درسی کتاب کا بھی ایک عنوان نہیں پڑھ پائے۔ یہی نہیں، کل بچوں کے 31 فیصدی ایسے بھی نکلے جو درجہ اول کی کتابوں میں لکھا بھی نہیں پڑھ پائے۔ نو ڈیٹینشن پالیسی کی وجہ سے درجہ سات اور آٹھ میں پہونچ گئے بچوں میں 50 فیصدی ایسے تھے جو اپنی ہی درسی کتاب سے ایک پیراگراف نہیں پڑھ پائے۔

دوسری طرف نصاب تعلیم یہ سوچ کر بنا ہے کہ بچوں کو پڑھنا آتا ہے۔ یہی نہیں ان سے یہ امید بھی کی جاتی ہے کہ وہ کتابوں سے خود پڑھ کر تمام باتوں کو سمجھ لیں گے۔ ظاہر ہے، پڑھنے میں اہل ہوئے بغیر کوئی طالب علم ایک انچ بھی نہیں بڑھ سکتا۔

یہی وجہ ہے کہ شعبہ تعلیم نے طالب علم کو پڑھنے میں اہل بنانے کیلئے اتنی محیط مہم چلائی۔ اگلے کچھ ہفتوں تک سبھی اسکولوں کے درجہ چھ سے آٹھ تک کے استاذ نے سرپرستوں اور برادری کے تعاون سے سبھی بچوں کو پڑھنا سیکھانے کی مہم چلائی۔ اس کا محیط اشاعت۔ نشر بھی کیا گیا۔ عوام سے اپیل بھی کی گئی کہ وہ اس مہم سے جوڑیں اور لوگ ارد گرد کے ایسے بچے کو مدد کریں جو اپنی کتاب ٹھیک سے نہ پڑھ پاتا ہو۔ اگلے دو مہینے تک شعبہ تعلیم کے 1016 اسکولوں میں درجہ چھ، سات اور آٹھ میں انرولمنٹیڈ 6.3 لاکھ بچوں میں سے قریب ساڑھے تین لاکھ بچوں کو پڑھانے میں ماہر بنانے کیلئے استاذ نے زبردست محنت کی۔ اس مہم کو باثر بنانے کیلئے 185 استاذ کا ریسورس گروپ بنایا گیا جنہیں 'منٹر ٹیچر' کہا گیا جنہیں پانچ اسکولوں کی ذمہ داری دی گئی انہوں نے مقررہ اسکول کے دو استاد اس مہم کیلئے تیار کیا۔ جنہوں نے کتابیں پڑھ پانے میں نااہل بچوں پر خاص توجہ دیا اور الگ الگ طرح کے صوم وصلوٰۃ کے ذریعہ انہیں پڑھنے میں ماہر ہونے کیلئے اکسایا۔

اس مہم کا ایک شاندار پہلو ریڈنگ میلا بطور سامنے آیا۔ انہیں اسکولوں کے علاوہ ہفتہ کے آخر میں محلوں میں بھی لگایا گیا۔ ایس ایم سی کے ذریعہ لوگوں کو اس میلوں سے جوڑا گیا۔ بچوں کا پڑھنا ایک دلچسپ تجربہ بن گیا مہم کے دوران کل 522 ریڈنگ میلوں کا انعقاد کیا گیا۔ ان میلوں میں 20000 ہزار سرپرستوں اور 71000 بچوں نے حصہ لیا۔

اسی دوران اسکولوں میں میگا پی ٹی ایم (پیرنٹ ٹیچر میٹنگ) منعقد کی گئی۔ ان میں سرپرستوں کو بچوں کی ترقی سے جڑی تمام باتوں کے علاوہ ان کے پڑھ پانے کی گنجائش کے بارے میں بھی جانکاری دی گئی۔

'پروجیکٹ اسمائل' سے چمکیں گے 35 ہزار بچے!

'ہر بچہ پڑھ سکتا ہے' مہم کے بعد دہلی سرکار نے اسکولی بچوں کیلئے 'پروجیکٹ اسمائل' شروع کیا ہے۔ یہ مہم ان بچوں پر دھیان مرکوز کرے گا جو صرف حروف پہچان سکتے ہیں لیکن سبق نہیں پڑھ پاتے۔ دہلی سرکاری اسکولوں میں ایسے 35000 ہزار بچے ایسے ہیں جن پر اس معاملے میں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

سرکار نے 5 ستمبر سے 14 نومبر کے بیچ 'ہر بچہ پڑھ سکتا ہے' مہم چلائی تھی جس میں ایک لاکھ سے زیادہ بچے اپنی کتابیں پڑھنے کے لائق بنے ہیں۔ سرکار نے اس سلسلے میں ریڈنگ میلا سمیت کئی ترکیب کی تھی لیکن بچے لفظ پہچان سے آگے نہیں بڑھ پائے۔ ایسے ہی 35000 ہزار بچوں کو پڑھنے میں اہل بنانے کیلئے 'پروجیکٹ اسمائل' شروع کیا گیا خاص طور سے تجربہ کار استاذ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔

وزیر تعلیم منیش سسودیا کا کہنا ہے کہ جب ہم نے 'ہر بچہ پڑھ سکتا ہے' مہم چلائی تھی تو کوشش کی تھی کہ ہر ضرورت مند بچے کو اس کا فائدہ ملے۔ اب 'پروجیکٹ اسمائل' کے ذریعہ پکا کیا جائے گا کہ ایک بھی بچہ چھوٹنے نہ پائے۔

ان بچوں کا خصوصی اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد ان کی قابلیت کے حساب سے الگ گروپ بنا کر انھیں اسپیشل ٹیچرس اور کونسلرس کو سونپ دیا جائے گا۔ جو خاص تکنک کی مدد سے ان کی پریشانی دور کریں گے۔ نظامت تعلیم میں ایک کنٹرول یونٹ ہوگی جو مہم پر نظر رکھے گی۔

Yogesh Kumar

रीडिंग मेले में खेल खेल में सीखा पढ़ना

■ प्रस, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार के एजुकेशनल कैंपेन 'रीडिंग मेले' में रविवार को स्टूडेंट्स अपने पैरंट्स के साथ पहुंचे। सरकार इन मेलों के साथ क्लास 6 से 8 तक के हर बच्चे को अपनी किताबें पढ़ने लायक बनाने की चुनौती को पूरा करने की कोशिश में है। हर बच्चे को पढ़ना सिखाने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर ने टीचर्स डे के दिन बाल दिवस यानी आज की डेडलाइन रखी थी। कैंपेन के तहत हर संडे रीडिंग मेले लगाए गए, करीब 250 मेलों में बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स और उनके पैरंट्स भी पहुंचे।

स्कूल मैनेजमेंट कमिटी ने इस मेलों को ऑर्गनाइज किया और कई ऐसे टूल और एक्टिविटी का इस्तेमाल किया ताकि बच्चे मजेदार तरीके से पढ़ना सीख सकें। मेलों में तमाम एक्टिविटी और गेम रखे गए ताकि बच्चा अक्षर, शब्द, वाक्य और पैराग्राफ पढ़ना सीख सकें। रविवार को नंद नगरी इलाके में लगे रीडिंग मेले में भी बच्चों ने खेल खेल में पढ़ना सीखा।

بدلی درجہ 6,7اور 8کی صورت

دہلی کے سرکاری اسکولوں میں درجہ 6,7اور 8میں پڑھنے والے تمام بچوں کی تعداد 632370 ہے۔"ہر بچہ پڑھ سکتا ہے" مہم کے تحت اس کے 57فیصدی یعنی 359152بچوں پر دھیان مرکوز کیا گیا جن کی ہندی میں لکھا سبق پڑھ لینے کی گنجائش کم تھی۔پانچ ستمبر سے لیکر چودہ نومبر کے بیچ چلے اس مہم کے نتیجے حوصلہ افزا رہے۔

درجہ 6-

- دہلی کے سرکاری اسکولوں میں درجہ چھ میں پڑھنے والے 25فیصدی بچوں ہی شان وشوکت سے اپنی کتاب پڑھ لیتے تھے۔مہم کے بعد ایسے بچوں کی تعداد 46فیصدی ہوگئی۔
- 32فیصدی بچے ایسے تھے جو کلاس ایک کی کتاب کا بھی ایک مضمون نہیں پڑھ سکتے تھے مہم کے بعد ایسے بچوں کی تعداد گھٹ کر 14فیصدی رہ گئی۔
- لفظ بھی نہیں پہچان سکنے والے بچوں کی تعداد آٹھ فیصدی سے گھٹ دو فیصدی رہ گئی۔

درجہ 7-

- درجہ سات کے 52فیصدی ہی پڑھنے میں اہل تھے۔مہم کے نتیجے میں یہ تخمینہ 64فیصدی ہوگیا۔
- 24فیصدی بچے ایسے بچے بھی تھے جو کلاس ایک کے معیار کی کتاب کا بھی ایک مضمون نہیں پڑھ سکتے تھے یہ تخمینہ گھٹ کر 10فیصدی رہ گیا۔
- لفظ بھی نہ پہچان سکنے والے بچوں کی تعداد پانچ فیصدی سے گھٹ کر ایک فیصدی رہ گئی۔

درجہ 8-

- درجہ آٹھ کے 55فیصدی بچے اپنا سبق پڑھ سکتے تھے،مہم کے بعد کل 68فیصدی بچے اپنی کتابیں پڑھنے میں اہل ہو گئے۔
- اس درجہ کے 20فیصدی بچے ایسے تھے جو کلاس ایک کے معیار کی کتاب نہیں پڑھ پاتے تھے۔مہم کے بعد یہ تخمینہ گھٹ کر آٹھ فیصدی رہ گیا۔
- کلاس آٹھ میں پہنچ گئے چار فیصدی بچے ایسے بھی تھے جنہیں لفظ کا پتا بھی نہیں تھا۔یہ تخمینہ محض ایک فیصدی رہ گیا۔

یہ کچھ مثال ہیں جو ٹیچرس ڈے یعنی 5ستمبر سے لیکر چلڈرنس ڈے یعنی 14نومبر کے بیچ دہلی کے درجہ چھ سے آٹھ میں پڑھنے والے سبھی اسکولی بچوں کو پڑھنے میں اہل بنانے کیلئے چلے محیط مہم کے دوران اُبھر کر آئے۔

ویسے ڈاکٹر رادھا کرشنن اور پنڈت جواہر لعل نہرو کو حوالے کردہ یہ دونوں دن ہر سال آتے ہیں،لیکن اس بار دہلی سرکار کے شعبہ تعلیم نے اس میں انوکھا رنگ بھر دیا۔ملک میں اپنی طرح کا انوکھا ''14نومبر 2016تک سبھی بچے پڑھیں گے،،مہم شروع کی گئی۔ٹیچرس ڈے پر نائب وزیراعلیٰ منیش سسودیا کی رہبری میں پوری شعبہ تعلیم نے حلف لیا کہ چلڈرنس ڈے تک سبھی بچوں کو باقاعدہ تیزی سے ہندی پڑھنے میں اہل بنادیا جائیگا۔

یہ ارادہ تعلیم کی حالت پر ایک بڑا حاشیہ تھا۔ابتدائی تعلیم میں پانچ برس گذار کر آنے والے بچوں سے یہ امید تو ہوتی ہے کہ وہ اپنی کتابیں پڑھ لیں گے۔

شاندار رہا 'ہر بچہ پڑھ سکتا ہے' ابھیان

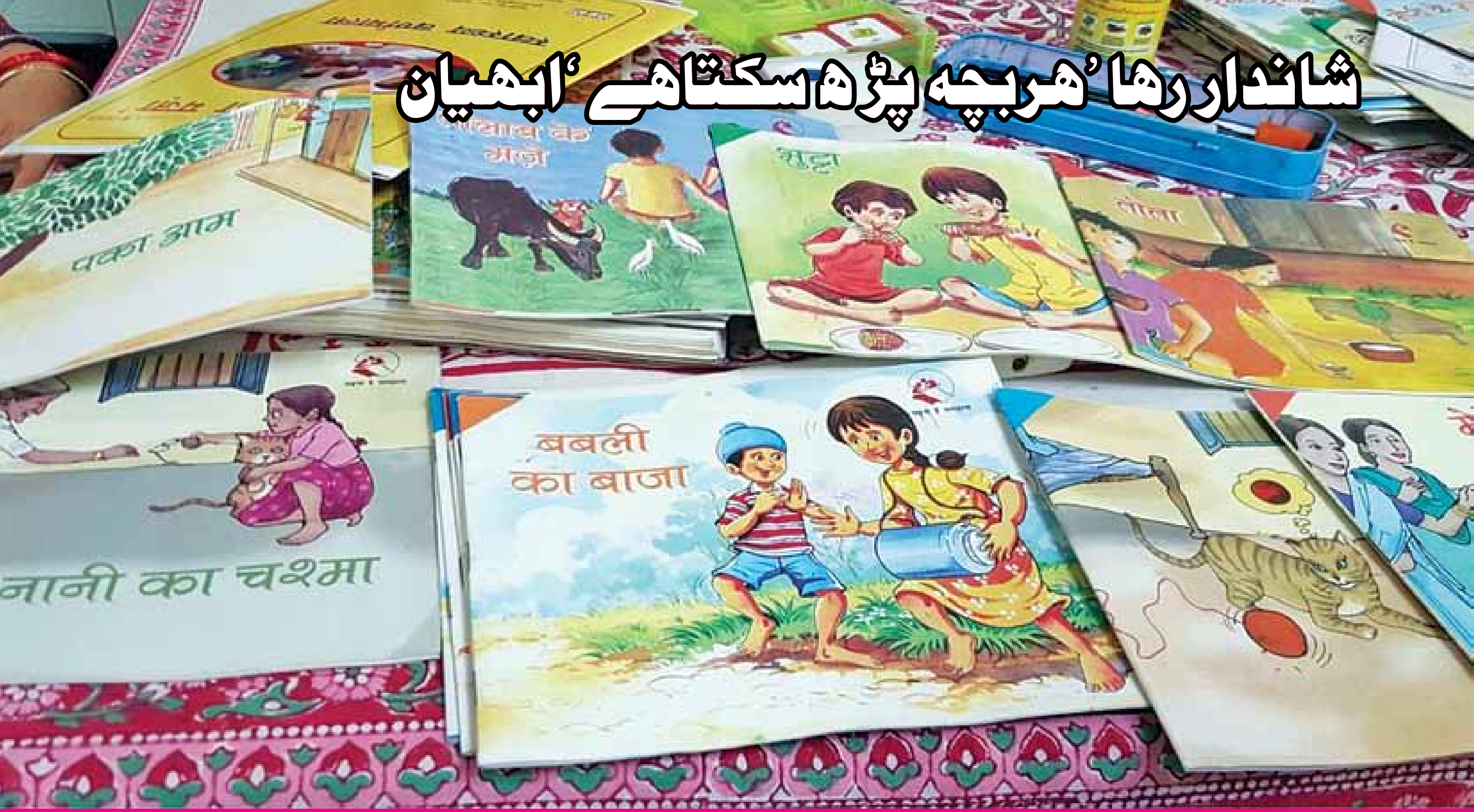

لفظوں سے دوستی، سبق سے پیار!

سرکاری اسکولوں کے 3.5 لاکھ بچوں نے جانا 'پڑھنے' کا مطلب

'میرے گروپ میں تین بچے ایسے ہیں جو دو ہفتہ پہلے صرف حروف پہچان پاتے تھے۔ اور ابھی بھی ان کا وہی حال ہے جب کی باقی بچے تیزی سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ ایسے میں، میں کیا کروں؟' واٹس ایپ گروپ میں ایک استاذ نے دوسرے استاذ کو اپنی پریشانی بتائی'

''ہمارے اسکول کا ایک بچہ پچھلے ایک ہفتہ سے اسکول نہیں آرہا ہے۔ اسکول ریکارڈ میں اس کے والد کا جو فون نمبر درج ہے وہ اب کام نہیں کر رہا ہے۔ کیا آپ اس بچے کو اسکول واپس لانے میں مدد کر سکتے ہیں؟'' ایک استاذ نے ایس ایم سی (اسکول مینجمنٹ کمیٹی) کے ممبر سے پوچھا۔

''اب میں روز اسکول آتا ہوں کیونکہ میرے ٹیچر مجھے نام سے بلاتے ہیں'' درجہ سات کے ایک طالب علم نے اسکول میں آرہے بدلاؤ اس طرح سے سمجھا۔

''میں خود نہیں پڑھ سکتی لیکن اپنے بیٹے سے اخبار پڑھوا کر سنتی ہوں۔ مجھے ایک مہینے میں کافی فرق دِکھ رہا ہے۔ اب وہ زیادہ خود اعتماد کے ساتھ پڑھتا ہے۔'' درجہ چھ کے ایک بچہ کی ماں نے خوشی ظاہر کی۔ ''میں حساب کا استاذ ہوں اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو سائنس پڑھاتا ہوں میں سوچتا تھا کہ اگر بچے کتاب پڑھ نہیں پاتے تو اس کی فکر ہندی کے استاذ کی ہونی چاہئے، اس سے میرا کیا لینا دینا۔ بحر حال پرنسپل نے درجہ آٹھ کے دس لڑکوں کو پڑھنے میں اہل بنانے کی ذمہ داری مجھے سونپی جسے میں نے بڑے من سے قبول کیا تھا لیکن اب مجھے محسوس ہوا کہ یہ ایک موقع تھا جس نے بچوں کو سمجھنے میں مدد کی۔ بچے ٹھیک سے پڑھنا سیکھ لیں گے تو میرے موضوع کو بھی بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے۔''

(इनर कवर की सभी तस्वीरें विश्व व्यापार मेले में बनाए गए सूचना एवं प्रचार निदेशालय के पविल्यन से।)

दिल्ली सरकार
आप की सरकार

दिल्ली सरकार
आप की सरकार

राज कुमार कसाना

ने 12 वीं पास करने के बाद दिल्ली सरकार के WCSC से एक साल का हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशन का कोर्स किया

जॉब प्रोफाइल: अमेरिका के प्रतिष्ठित क्रूज शिप में क्रू मेम्बर

पैकेज: 14 लाख रुपए प्रति वर्ष

गुंजन सागर

ने 12 वीं पास करने के बाद दिल्ली सरकार के WCSC से एक साल का हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशन का कोर्स किया

जॉब प्रोफाइल: प्रतिष्ठित एयरलाइन्स में ट्रेनी केबिन क्रू

पैकेज: 4.40 लाख रुपए प्रति वर्ष

खुशबू अटल

ने 12 वीं पास करने के बाद दिल्ली सरकार के WCSC से एक साल का फाइनेंस एक्जीक्यूटिव का कोर्स किया

जॉब प्रोफाइल: प्रतिष्ठित फाइनेंस फर्म में अकाउंट एक्जीक्यूटिव

पैकेज: 4.80 लाख रुपए प्रति वर्ष

ADMISSION OPEN

एक वर्षीय फुल टाइम सर्टिफिकेट कोर्स

वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर (WCSC)

(सिंगापुर सरकार के सहयोग से)

योग्यता: 12 वीं पास (सभी वर्ग)

इनफार्मेशन पुस्तिका सहित आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें- **www.tte.delhigovt.nic.in**

अंतिम तिथि : 27 फ़रवरी 2017

कोर्सेस

- हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशंस
- रिटेल सर्विसेस
- सॉफ्टवेयर टेस्टिंग असिस्टेंट
- फाइनेंस एक्जीक्यूटिव

वर्ल्डक्लास स्किल सेंटर की ख़ासियत:

- ❒ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी (पूर्ण वातानुकूलित और स्मार्ट क्लास रूम, लिफ्ट, पीने का साफ़ पानी, कैफेटेरिया)।
- ❒ लेटेस्ट और सबसे एडवांस ट्रेनिंग के लिए उपकरण।
- ❒ ITE सिंगापुर द्वारा तैयार स्पेशलाइज्ड कोर्सेस के लिए पाठ्यक्रम।
- ❒ ITE सिंगापुर द्वारा प्रशिक्षित योग्य मास्टर ट्रेनर्स।
- ❒ ITE सिंगापुर द्वारा संयुक्त निगरानी में ट्रेनिंग
- ❒ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम।
- ❒ नामी इन्डस्ट्रीज और होटल्स में 3 महीने की इंटर्नशिप।
- ❒ देश-विदेश में बहुराष्ट्रीय नामी कंपनियों, बड़े रिटेलर्स, 5 स्टार होटल्स में रोज़गार के अवसर।
- ❒ कई स्टूडेंट्स विदेशों में नौकरी पा चुके हैं।

प्रशिक्षण और तकनीकी
शिक्षा निदेशालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

डॉ. जयदेव षड़ंगी, निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054 द्वारा प्रकाशित एवं आकांक्षा इम्प्रेशन्स, 18/36 स्ट्रीट नं. 5, रेलवे लाइन साइड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली–05 द्वारा मुद्रित